**प्रश्न:**1 हीटवेव की बढ़ती आवृत्ति के साथ-साथ हीटवेव के समय से पहले और तीव्र होने के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। (150 शब्द)

* **आईएमडी द्वारा हीट वेव की चेतावनी - समसामयिकी लेख**
* 21 फरवरी के सप्ताह में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी थी कि उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान दीर्घकालिक औसत से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा।

## मुख्य विचार:

* 21 फरवरी को ही, राष्ट्रीय राजधानी ने पांच दशकों से अधिक समय में अपना तीसरा सबसे गर्म फरवरी दिन (33.6 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया।
* एक हफ्ते पहले, आईएमडी ने कच्छ और कोंकण क्षेत्रों में गर्म हवाओं की चेतावनी दी थी, लेकिन समुद्री हवा के बचाव में आने के बाद उन्हें वापस ले लिया गया।
* भले ही ये असामान्य घटनाएँ हों, भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म लहरों के अधिक तीव्र, लंबे और अधिक बारंबार होने की संभावना है।

## हीट वेव्स क्या हैं?

* आईएमडी के अनुसार, एक क्षेत्र में गर्मी की लहर होती है यदि उसके परिवेश का तापमान लंबी अवधि के औसत से कम से कम 4.5-6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है।
* यदि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस (या किसी हिल स्टेशन पर 37 डिग्री सेल्सियस) को पार कर जाता है तो लू भी चलती है।

## पूर्व-परिपक्व और गहनता:

* हीट वेव 'सीज़न' 2022 में पहले शुरू हुआ था और लंबी अवधि के औसत से अधिक तीव्र था, और अधिक लहरें थीं।
* ला नीना द्वारा स्थापित उत्तर-दक्षिण दबाव पैटर्न के कारण गर्मी की लहरें प्रायद्वीपीय भारत में बहुत आगे बढ़ गईं , एक विश्व-प्रभावित मौसम की घटना जिसमें ठंडे पानी का एक बैंड पूर्व-पश्चिम में फैलता है। भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के पार।
* पिछले तीन साल ला नीना साल रहे हैं, जिसने 2023 के अग्रदूत के रूप में काम किया है, जो अल नीनो वर्ष होने की संभावना है। (एल नीनो एक पूरक घटना है जिसमें गर्म पानी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम-पूर्व में फैलता है।)
* एल नीनो वर्षों में गर्म लहरें उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत तक ही सीमित रहती हैं।

## हीट वेव के गठन के कारण :

* गर्म हवा कहीं और से बह रही है या क्योंकि कुछ स्थानीय रूप से इसका उत्पादन कर रहा है।
* हवा को स्थानीय रूप से गर्म किया जाता है जब हवा को उच्च भूमि की सतह के तापमान से गर्म किया जाता है या क्योंकि ऊपर से डूबने वाली हवा रास्ते में संकुचित होती है, जिससे सतह के पास गर्म हवा पैदा होती है।

## प्रकृति भूविज्ञान द्वारा अध्ययन : हीट वेव के निर्माण में विभिन्न प्रक्रियाएं कैसे योगदान करती हैं?

### 1. गर्म हवा का स्रोत:

* वसंत में, भारत में आमतौर पर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से हवा बहती है जो भारत के लिए प्रतिकूल है क्योंकि भूमध्य रेखा के समान अक्षांशों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मध्य पूर्व तेजी से गर्म हो रहा है, और भारत में बहने वाली गर्म हवा के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

### 2. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ों की भूमिका:

* उत्तर-पश्चिम से बहने वाली हवा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है, जिससे इन पहाड़ों के लेवर्ड साइड पर संपीड़न होता है, जो भारत में तेज गर्मी के साथ प्रवेश करता है।

### 3. अरब सागर का गर्म होना:

* महासागरों के ऊपर बहने वाली हवा से ठंडी हवा आने की उम्मीद है, क्योंकि भूमि महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म होती है, और इस प्रकार, अरब सागर अधिकांश अन्य महासागर क्षेत्रों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है।

### 4. ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ हवाओं की भूमिका:

* तेज ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ हवाएं जो वसंत के दौरान अटलांटिक महासागर से भारत में आती हैं, निकट-सतही हवाओं को नियंत्रित करती हैं।
* किसी भी समय हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, हवाएं ग्रह की तुलना में तेज चल रही हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर भी घूम रही है।
* सतह के पास पृथ्वी के पास से गुजरने की ऊर्जा, सतह के घर्षण के विरुद्ध, केवल ऊपर से ही आ सकती है।
* यह अवरोही हवा कुछ ऊष्मा तरंगें उत्पन्न करने के लिए संकुचित और गर्म होती है।

### 5. घटती चूक दर:

* लैप्स रेट, वह दर जिस पर तापमान सतह से ऊपरी वायुमंडल तक ठंडा होता है, ग्लोबल वार्मिंग के तहत घट रहा है।
* दूसरे शब्दों में, ग्लोबल वार्मिंग सतह के पास की हवा की तुलना में ऊपरी वायुमंडल को तेजी से गर्म करती है।
* बदले में इसका मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूबती हवा गर्म है, और इस प्रकार गर्मी की लहरें उत्पन्न होती हैं क्योंकि यह डूबती है और संकुचित होती है।

## ताप तरंगों के निर्माण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक :

* गर्मी की लहरों के गठन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक वायु द्रव्यमान की आयु और कितनी दूर तक यात्रा कर चुके हैं।
* उत्तर-पश्चिमोत्तर ताप तरंगें आमतौर पर वायुराशियों से बनती हैं जो 800-1,600 किमी दूर से आती हैं और लगभग दो दिन पुरानी होती हैं।
* दूसरी ओर प्रायद्वीपीय भारत में गर्म तरंगें महासागरों से आती हैं, जो करीब (लगभग 200-400 किमी) हैं और बमुश्किल एक दिन पुरानी हैं। नतीजतन, वे औसतन कम तीव्र होते हैं।
* इन ऊष्मा तरंगों से आच्छादित क्षेत्र अल नीनो और ला नीना घटनाओं द्वारा स्थापित पृष्ठभूमि दबाव पैटर्न से भी प्रभावित होता है, और बाद में इसका विस्तार होता रहा है।

## निष्कर्ष:

* हीट वेव्स का एक परिष्कृत शरीर रचना है जिसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं कि हम कितनी अच्छी तरह उनका अनुमान लगा सकते हैं।
* बहरहाल, पूर्व-चेतावनी प्रणालियां चेतावनियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रक्रियाओं, गठन के तरीकों, स्थान और वायु द्रव्यमान की आयु का लाभ उठा सकती हैं और यह भी बढ़ा सकती हैं कि उन्हें कितनी जल्दी जारी किया जा सकता है।
* मानव और कम्प्यूटेशनल संसाधनों में बड़े निवेश ने पिछले दशक में भारत के पूर्वानुमान कौशल को पहले ही बढ़ा दिया है।
* जिन कारणों से हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, भारत में गर्मी की लहरों के कारण मृत्यु दर अन्य मध्य-अक्षांश क्षेत्रों (संभावित महत्वपूर्ण अंडररिपोर्टिंग सहित) की तुलना में काफी कम है।
* हमें भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, और आगे, पूर्वानुमान चेतावनियों में सुधार करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें जारी करना चाहिए, और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें शहर-व्यापी ग्रेडेड हीट एक्शन प्लान के साथ जोड़ना चाहिए।

**प्रश्न:** 2 फसलों में एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो भारत के कृषि क्षेत्र को एक स्थायी और समावेशी बढ़ावा दे सकता है। मूल्यांकन करें। (150 शब्द)

# मध्य प्रदेश के कृषि मॉडल से सबक - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

* मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कृषि में उच्चतम विकास दर 7.3 प्रतिशत दर्ज की है । राज्य के कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि के पीछे फसलों में एक अच्छी तरह से विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो है। यह समावेशी और टिकाऊ है और अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है।

## मुख्य विचार:

* आईएमएफ के अनुसार, भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है और 2027 तक इसके 5.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
* जबकि बाहरी कारक जैसे कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष भारत के 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में कुछ देरी कर सकते हैं, यह प्राप्त करने योग्य है।
* 2006 में भारत को 0.95 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में आज़ादी के बाद से लगभग 59 साल लग गए, लेकिन फिर अगले दशक में इसमें 1.35 ट्रिलियन डॉलर जुड़ गए, 2016 तक यह 2.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गई, और फिर 2022 में $ 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई, जिसमें 1.2 ट्रिलियन डॉलर शामिल थे ।
* यदि भारत इस रास्ते पर रहता है, तो देश 2047 तक $25 से $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक बढ़ सकता है।
* हालाँकि दो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है । पहला, यह विकास कितना समावेशी है, और दूसरा, यह कितना टिकाऊ होने की संभावना है, विशेष रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से, यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।

## समावेशन को मापना:

* बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) और कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करके मापा जाता है , जो कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से (2020-21 में 46.5%) को रोजगार देता है।
* देश ने प्रति वर्ष 6.7% की औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल की, जबकि इसकी कृषि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.8% प्रति वर्ष थी। हालांकि यह प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन यह चीन में देखी गई असाधारण वृद्धि के बराबर नहीं है।
* कुल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद उत्तराखंड, तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।
* इस सूची में सबसे नीचे जम्मू-कश्मीर, असम पश्चिम, उत्तर प्रदेश और झारखंड थे।
* इस वृद्धि की समावेशिता का आकलन करने के लिए , बीमारू राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की जांच करने की आवश्यकता है।
* इन राज्यों में, मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है , कृषि में उच्चतम विकास दर 7.3% प्राप्त की है। इसकी समग्र जीडीपी वृद्धि भी 7.5% पर सराहनीय है।
* राजस्थान ने भी 5.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज करते हुए कृषि में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद क्रमश: 4.5 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।
* झारखंड ने 6.4 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर के साथ कृषि में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जो मुख्य रूप से बागवानी और पशुधन की ओर विविधीकरण से प्रेरित है।

## पंजाब का केस स्टडी

* हरित क्रांति चैंपियन पंजाब ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस अवधि में इसकी कृषि-जीडीपी वृद्धि मात्र 2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।
* राज्य में पहले से ही गेहूं और चावल में उच्च स्तर की उत्पादकता है, और कृषि में और अधिक विकास संभव नहीं है।
* यदि पंजाब ने उच्च मूल्य वाली बागवानी में विविधता लाई होती या अपने कृषि पोर्टफोलियो में कुछ दालों और तिलहन को शामिल किया होता, तो यह अधिक कृषि विकास हासिल कर सकता था और, महत्वपूर्ण रूप से, कीमती भूजल संसाधनों और बिजली सब्सिडी का संरक्षण करता।
* धान की खेती से होने वाले मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता के बारे में सोचने और सोचने की जरूरत है।

## मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल:

* टमाटर, लहसुन, मैंडरिन संतरे, दालें (विशेष रूप से चना) और सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थापित किया है ।
* एमपी भी गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (यूपी के बाद) है, और यूपी और राजस्थान के बाद तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक है।
* इसके अतिरिक्त, दालें और तिलहन अपने नाइट्रोजन-फिक्सिंग गुणों और कम पानी के उपयोग के लिए जाने जाते हैं, जिससे उर्वरक और बिजली सब्सिडी की आवश्यकता कम हो जाती है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
* पिछले दो दशकों में अपने सकल फसली क्षेत्र के 24 से 45.3 प्रतिशत तक सिंचाई कवरेज को दोगुना करते हुए कृषि में एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो का अनुसरण कर रहा है ।

## निष्कर्ष:

* मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान अखिल भारतीय स्तर पर 18.8 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है - इसके मॉडल को उपयुक्त रूप से समावेशी और टिकाऊ के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।
* राज्य की कृषि-जीडीपी वृद्धि अखिल भारतीय कृषि-जीडीपी वृद्धि से अधिक है , और यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के मूल्य में बागवानी के योगदान को दोगुना करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

**प्रश्न:**3 गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक जलवायु दशाओं की चर्चा कीजिए। समय से पहले गर्मी से निपटने के उपाय सुझाएं। (150 शब्द)

# गेहूं की फसल का परिदृश्य अच्छा है लेकिन जलवायु एक चुनौती पेश कर सकती है - समसामयिकी लेख

* पश्चिमी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फरवरी में बढ़ते तापमान ने एक बार फिर गेहूं की फसल को लेकर चिंता बढ़ा दी है , हालांकि केंद्र ने इस सीजन में 112 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन की भविष्यवाणी की है।

## मुख्य विचार:

* मार्च और अप्रैल में एक अभूतपूर्व गर्मी की लहर के परिणामस्वरूप केंद्र द्वारा 111 मिलियन टन के प्रारंभिक उत्पादन के अनुमान के बाद पिछले साल 107 मिलियन टन का उत्पादन कम हो गया ।
* मार्च और अप्रैल में उच्च तापमान और कम वर्षा के अत्यधिक संयोजन के कारण पिछले साल गेहूं की पैदावार 15-25 प्रतिशत गिर गई थी।
* यह 36 मौसम उपखंडों में से 10 में दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दूध, पोल्ट्री, फल और सब्जियों के मामले में उपज में गिरावट देखी गई।

## गेहूँ

* गेहूं एक रबी फसल है जो सितंबर और दिसंबर के बीच उगाई जाती है और फरवरी और मई के बीच काटी जाती है।
* भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं।

## जलवायु आवश्यकताएँ:

* सबसे अच्छे गेहूं का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां फसल उगाने की अवधि के प्रमुख हिस्से के दौरान ठंडा, नम मौसम होता है और उसके बाद सूखा, गर्म मौसम अनाज को ठीक से पकने में सक्षम बनाता है।
* गेहूं के बीज के आदर्श अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान सीमा 20-25 सी है , हालांकि बीज तापमान 5 से 35 सी में अंकुरित हो सकते हैं।
* बुवाई के तुरंत बाद बारिश अंकुरण में बाधा डालती है और पौध झुलसा को प्रोत्साहित करती है। गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्र गेहूँ उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।

## मिट्टी की आवश्यकताएं:

* मिट्टी दोमट या दोमट बनावट, अच्छी संरचना और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आदर्श होती है।
* खराब संरचना और खराब जल निकासी वाली भारी मिट्टी उपयुक्त नहीं है क्योंकि गेहूं जल जमाव के प्रति संवेदनशील है।

## सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्रायलैंड एग्रीकल्चर (क्रीडा)

* CRIDA भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1985 में बारानी खेती में बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए की गई थी।
* संस्थान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परामर्शी परियोजनाएं भी चलाता है।
* यह अग्रणी संस्थान है और जलवायु अनुकूल कृषि (एनआईसीआरए) में राष्ट्रीय नवाचारों के लिए राष्ट्रीय नोडल बिंदु है जिसे बड़ी संख्या में आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 100 केवीके के अनुसंधान संस्थानों में लागू किया जा रहा है।

## कारण :

* 2022 में फरवरी और मार्च में बारिश लाने और सर्दियों की स्थिति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ अनुपस्थित थे।
* वे भारत के मौसम और कृषि को संतुलन में रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
* इनकी गैरमौजूदगी में अरब के रेगिस्तान से एक गर्म, उच्च दबाव वाला 'एंटी-साइक्लोन' आता है। इस साल भी पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहा है।
* फसलों को तत्काल कोई खतरा नहीं है क्योंकि इस महीने रातें ठंडी रही हैं, यहां तक कि उत्तरी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहा है ।

## पश्चिमी विक्षोभ क्या है?

* एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है, जो पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी नेपाल के उत्तरी भागों तक फैला हुआ है।
* यह एक गैर-मानसूनी वर्षा पैटर्न है जो पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित है। इन तूफानों में नमी आमतौर पर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर के ऊपर उत्पन्न होती है।
* अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान एक वैश्विक घटना है जिसमें आमतौर पर ऊपरी वायुमंडल में नमी होती है, उनके उष्णकटिबंधीय समकक्षों के विपरीत जहां निचले वातावरण में नमी होती है।
* भारतीय उपमहाद्वीप के मामले में, जब तूफान प्रणाली हिमालय से टकराती है तो नमी कभी-कभी बारिश के रूप में बहा दी जाती है। सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ अधिक बार और मजबूत होते हैं।

## तैयारी :

* मार्च के अंत तक 15-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान गेहूं के लिए आदर्श होता है।
* कुछ मौसम वैज्ञानिकों का तर्क है कि सर्दियों के महीनों में पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति कम होने की उम्मीद है। इसलिए, गर्मी की समय से पहले शुरुआत से निपटने के लिए रबी के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
* एक आईसीएआर परियोजना उत्तर और पश्चिम भारत में 151 जलवायु-जोखिम-प्रवण ग्राम समूहों में गर्मी प्रतिरोधी किस्मों और अन्य तकनीकों पर काम कर रही है।
* गर्मी को मात देने का एक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि गेहूं जल्दी बोया जाए।
* कम अवधि वाली किस्मों के साथ धान की सीधी बुआई करने से अक्टूबर के अंत में गेहूं की बुआई करने में मदद मिलती है।
* नवंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में बोई गई फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
* चावल की जल्दी कटाई के तुरंत बाद 'हैप्पी सीडर' के साथ गेहूं की फसल की तेजी से बुआई करने से पिछले साल लगभग सामान्य पैदावार (97 प्रतिशत) हुई।
* गर्मी सहने वाली किस्मों से भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ मल्चिंग और छायांकन जैसी गर्म-से-गर्मी प्रथाओं को लोकप्रिय बनाना महत्वपूर्ण है ।

## निष्कर्ष:

* 34.1 मिलियन हेक्टेयर के रकबे के साथ गेहूं की फसल अच्छी दिख रही है, जो पिछले साल की तुलना में मामूली अधिक है।
* ऐसे संकेत हैं कि अगेती बुवाई में तेजी आई है, लेकिन कृषि पद्धतियों को नई जलवायु वास्तविकताओं के अनुकूल होने की आवश्यकता है।

**प्रश्न:**4 UPI- PayNow लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विस्तार में बतायें। (250 शब्द)

# एक बार्डर लेस: यूपीआई-पे नाउ लिंकेज - समसामयिकी लेख

* केंद्र सरकार ने सिंगापुर के PayNow भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के साथ भारत के पहले क्रॉस-बॉर्डर रीयल-टाइम भुगतान सिस्टम लिंकेज का अनावरण किया है।

## मुख्य विचार:

* यह कनेक्टिविटी, जो केवल यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, या आभासी भुगतान पते का उपयोग करके धन के हस्तांतरण की अनुमति देगी, का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सीमाओं के पार धन हस्तांतरण के लिए "कम लागत वाला वास्तविक समय" विकल्प प्रदान करना है ।
* यह एक उत्साहजनक विकास है।

## यूपीआई क्या है?

* यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत की मोबाइल-आधारित तेज़ भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है।
* यह प्रेषक द्वारा बैंक खाता विवरण साझा करने के जोखिम को समाप्त करता है।
* UPI पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान दोनों का समर्थन करता है और यह उपयोगकर्ता को पैसे भेजने या प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।
* यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित और RBI द्वारा विनियमित है।
* NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI लॉन्च किया था।
* भारत विदेशों में UPI- आधारित बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है जैसे कि सिंगापुर के PayNow को UPI से जोड़ा गया है।

## यूपीआई और इसकी उपलब्धियां

* 2016-17 में यूपीआई की शुरुआत से देश के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया।
* धन , आधार और मोबाइल फोन की JAM त्रिमूर्ति के साथ , यह भुगतान संरचना देश में डिजिटल भुगतान की नाटकीय वृद्धि को सुविधाजनक बनाने में सहायक रही है, जो एक अनुकूल नियामक ढांचे द्वारा सहायता प्राप्त है।
* जनवरी 2023 में, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 बिलियन लेनदेन किए गए, जिसका मूल्य लगभग 13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
* भुगतानों के वास्तविक समय हस्तांतरण की सुविधा, उपयोगकर्ताओं के लिए शून्य-लागत ढांचा, और स्वीकृति स्पर्श-बिंदुओं में तेजी से विस्तार ने इसके व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित किया है।
* इसने कम लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन में तेजी लाने में भी सहायता की है।

## PayNow क्या है?

* PayNow सिंगापुर में एक तेज़ भुगतान प्रणाली है।
* यह पीयर-टू-पीयर फंड ट्रांसफर सेवा को सक्षम बनाता है, जो सिंगापुर में भाग लेने वाले बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनएफआई) के माध्यम से खुदरा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।
* यह उपयोगकर्ताओं को केवल अपने मोबाइल नंबर, सिंगापुर राष्ट्रीय पंजीकरण पहचान पत्र (NRIC)/विदेशी पहचान संख्या (FIN), या VPA का उपयोग करके सिंगापुर में एक बैंक या ई-वॉलेट खाते से दूसरे बैंक में तत्काल धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।

## यूपीआई- पेनाउ लिंकेज क्या है?

* सीमा पार खुदरा भुगतान आम तौर पर घरेलू लेनदेन की तुलना में कम पारदर्शी और अधिक महंगे होते हैं।
* UPI- PayNow लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और तेजी से, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान चलाने की G20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

## लिंकेज के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :

* RBI ने स्पष्ट किया है कि UPI- PayNow इंटरलिंकेज लेनदेन में, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत "रिश्तेदारों के रखरखाव" और " उपहार" के उद्देश्य से केवल व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) प्रेषण की अनुमति है, और निर्धारित एलआरएस सीमा लागू होगी।
* बैंक खातों या ई-वॉलेट में रखी गई धनराशि को केवल यूपीआई-आईडी, मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके भारत से और भारत से स्थानांतरित किया जा सकता है।
* वर्तमान में, फोनपे , गूगल पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लिंकेज के तहत सीमा पार लेनदेन संभव नहीं है ।

## उदारीकृत विप्रेषण योजना [एलआरएस]

* एलआरएस भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक कार्यक्रम है जो भारत को और भारत से धन के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है ।
* यह योजना लेन-देन की लागत को कम करने, धन हस्तांतरण की गति बढ़ाने और भारत में निवेश के आकर्षण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी ।

## दोनों देशों के नागरिकों को कैसे लाभ होगा?

* UPI- PayNow लिंकेज दो तेज भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली पर जाने की आवश्यकता के बिना पारस्परिक आधार पर तत्काल, कम लागत वाले फंड ट्रांसफर करने में सक्षम करेगा।
* यह सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को सिंगापुर से भारत में तत्काल और कम लागत वाले धन के हस्तांतरण के माध्यम से और इसके विपरीत मदद करेगा।
* आरबीआई रेमिटेंस सर्वे, 2021 के अनुसार, 2020-21 में भारत में कुल आवक प्रेषण में सिंगापुर का हिस्सा 5.7 प्रतिशत था।

**प्रश्न:**5 भारत में अंग प्रत्यारोपण नियमों पर चर्चा करें। अंग प्रत्यारोपण के नियमों में बदलाव क्यों जरूरी था? (250 शब्द)

# अंग प्रत्यारोपण नियमों में परिवर्तन - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

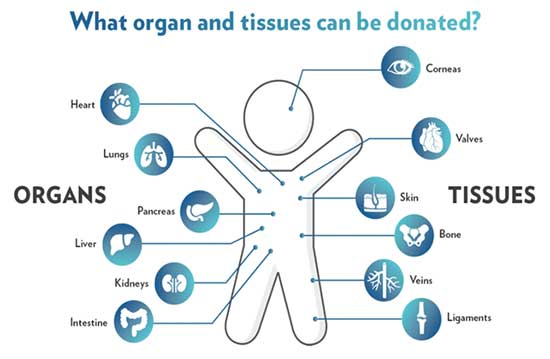
* केंद्र ने अपने ' एक राष्ट्र, एक अंग आवंटन नीति' नियम के तहत देश में अंग प्रत्यारोपण नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें प्राप्तकर्ताओं के लिए 65 साल की उम्र की सीमा को हटा दिया गया है और उन्हें न केवल अपने राज्य में बल्कि किसी भी राज्य में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है।
* इस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक अब जीवित दाताओं से दान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

## मुख्य विचार:

* स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अंगदान नियमों के तहत तीन अहम बदलाव किए गए हैं।
* अंगों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने और देश में शव दान को बढ़ावा देने के लिए बदलाव किए गए थे, जो इस समय संख्या में काफी कम है।
* जिन प्रावधानों में बदलाव किया गया है, उनमें से एक यह है कि अब कोई भी प्राप्तकर्ता अंग प्रत्यारोपण के लिए अपनी पसंद के किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकता है। अब, रजिस्ट्री अखिल भारतीय होगी न कि राज्य-विशिष्ट।
* इससे पहले, कुछ राज्यों ने या तो उन प्राप्तकर्ताओं को पंजीकृत किया जो वहां रहते थे या उन्हें अंगों के आवंटन में प्राथमिकता दी गई थी।
* महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य अंग प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले रोगियों को पंजीकृत करने के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच शुल्क लेते हैं ।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को यह शुल्क वसूलना बंद करने का निर्देश दिया है।
* भारत हर साल दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा प्रत्यारोपण करता है।
* फिर भी जिन रोगियों को लिवर, हृदय या गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है उनमें से मुश्किल से चार प्रतिशत ही इसे प्राप्त कर पाते हैं।
* हाल ही में घोषित नियमों में बदलाव प्रभावी होने के बाद प्रतिशत बढ़ने की बहुत संभावना है।

## अंग दान क्या है?

* अंग दान एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो लोगों को मृत्यु के बाद अपने स्वस्थ अंगों को ज़रूरतमंद लोगों को देने की अनुमति देता है, जो अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करने के लिए चिकित्सकीय रूप से सही हैं।
* एक अंग प्रत्यारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी के बेकार अंग या ऊतक को एक दाता से स्वस्थ अंग के साथ बदलना शामिल है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना है कि अंग मानव शरीर के अंदर अपना काम करना जारी रख सके।
* एक एकल अंग दाता प्रत्यारोपण के लिए पच्चीस विभिन्न अंगों और ऊतकों को दान कर सकता है।
* संचयी रूप से, इन अंगों और ऊतकों में आठ अलग-अलग जीवन बचाने की क्षमता होती है! गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय, फेफड़े और हृदय सामान्य दान योग्य अंग हैं।
* दान योग्य ऊतकों में आंखें, त्वचा, हड्डी, अस्थि मज्जा, तंत्रिकाएं, मस्तिष्क, हृदय वाल्व, कान का परदा, कान की हड्डियां और रक्त के ऊतक शामिल हैं।



## क्या आप जानते हैं?

* अंग प्रत्यारोपण की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2022 में 15,561 हो गई है।
* जीवित दाताओं से गुर्दा प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 3,495 से बढ़कर 2022 में 9,834 हो गई है और मृत दाताओं से, यह 2022 में 542 से बढ़कर 1,589 हो गई है।
* जीवित दाताओं से लीवर प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 658 से बढ़कर 2022 में 2,957 और मृत दाता से 2022 में 240 से 761 हो गई है।
* हृदय प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 30 से बढ़कर 2022 में 250 हो गई है जबकि फेफड़े के प्रत्यारोपण की संख्या 23 से बढ़कर 138 हो गई है।

## देश का अंग स्थानांतरण कानून

* देश का अंग हस्तांतरण कानून रोगी के करीबी रिश्तेदारों - माता-पिता, जीवनसाथी और भाई-बहनों द्वारा दान को मान्यता देता है ।
* मामले में, एक निकट संबंधी चिकित्सकीय रूप से प्राप्तकर्ता के साथ असंगत है, जोड़ी को एक अन्य संबंधित बेजोड़ जोड़ी के साथ स्वैप प्रत्यारोपण की अनुमति है।
* लेकिन कुल मिलाकर, देश में अधिकांश अंगदान मरीजों के करीबी रिश्तेदारों द्वारा नहीं किए जाते हैं।
* ऐसे दाताओं को अपने परोपकारी उद्देश्यों के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी को विश्वास दिलाना होगा।

## अंगदान में चुनौतियाँ:

* जागरूकता की कमी: जागरूकता की कमी और अंधविश्वासों का एक आवरण जो भारतीय आबादी पर खींचा जाता है, देश में अंगों की अनुपलब्धता के प्रमुख कारण हैं।
* कुछ लोगों को धार्मिक अंधविश्वास होता है जैसे कि अगले जन्म में उन्हें वह अंग नहीं मिलेगा जो वे दान करते हैं।
* भरोसे की कमी: रोगी के परिवार और चिकित्सा पेशेवरों के बीच विश्वास की भी कमी है।
* परिवार वाले अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर वे रोगी के अंगों को दान करने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं, तो डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे।

## आगे की राह:

* नियमों में बड़े बदलाव लाने के अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने की योजना बना रहा है।
* स्कूली पाठ्यक्रम और चिकित्सा शिक्षा में अंग दान पर एक अध्याय शुरू करने का सुझाव दिया है ।
* नियमित घोटालों ने एक काले बाजार पर प्रकाश डाला है जो लेन-देन को परोपकारी बताते हुए अपने अंगों को बेचने के लिए बेहद गरीबों को लुभाता है।
* समितियों की कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी बनाने के सुझावों को अधिकारियों द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है।
* लेकिन देश में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते बोझ का मतलब है कि ऐसे कार्यों को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है।
* अंगों के पूल को बढ़ाने के लिए नैतिक अनिवार्यताओं से समझौता किए बिना विनियामक रचनात्मकता की आवश्यकता होगी।
* ऑप्ट-आउट सिस्टम - यह सभी नागरिकों को दाता मानता है जब तक कि वे "ऑप्ट-आउट" नहीं करते - कुछ पश्चिमी देशों में अपनाया गया भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, जहां अंग दान के बारे में जागरूकता कम है। लेकिन आने वाले भविष्य में इसका समाधान जरूर हो सकता है।

## निष्कर्ष:

* अंग की कमी की समस्या, हालांकि, एक जटिल है, जो योजनाकारों को भ्रमित करना जारी रखती है, यहां तक कि उन देशों में भी जिनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भारत की तुलना में कहीं बेहतर है।
* हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित अंग प्रत्यारोपण नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण हैं, असफल अंगों वाले कई लोगों को जीवन का एक नया पट्टा देने की दिशा में कदम।

**प्रश्न:**6 भारत में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करें। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन से विभिन्न कदम उठाए हैं? ( 250 शब्द

# ग्रामीण पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए गांवों की क्षमता का दोहन - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

* केंद्रीय नोडल एजेंसी - रूरल टूरिज्म एंड रूरल होमस्टे (सीएनए - आरटी और आरएच), केंद्र, राज्यों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वयक निकाय, ने ग्रामीण भारत की यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों के लिए कृषि पर्यटन , कला और संस्कृति इकोटूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल टूरिज्म और होमस्टे सहित छह विशिष्ट अनुभवों की पहचान की है।

## मुख्य विचार:

* 134 से अधिक गांवों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर्यटकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है।
* उदाहरण के लिए,
* तमिलनाडु का कोलुक्कुमलाई दुनिया का सबसे ऊंचा चाय बागान है;
* केरल का देवलोकम एक नदी के किनारे योग केंद्र है;
* नागालैंड का कोन्याक टी रिट्रीट आगंतुकों को आदिवासी संस्कृति की यात्रा पर ले जाता है;
* तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव ने अपनी पारंपरिक बुनाई तकनीक का प्रदर्शन किया; और
* हिमाचल प्रदेश का प्रागपुर गांव पर्यटकों को कांगड़ा विरासत वास्तुकला से रूबरू कराता है।
* मत्तूर कर्नाटक का एक गाँव है जहाँ के निवासी केवल संस्कृत में बात करते हैं।
* माचली नारियल, सुपारी और केले के बागानों से घिरा एक कृषि गृह है।
* के बिश्नोई गांव में लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से अक्सर दौरा होता है।
* ये ऐसे गंतव्य हैं जहां पर्यटक खुद को ग्रामीण पर्यटन अनुभव में डुबो सकते हैं जिसे सरकार अब विकसित कर रही है।
* अनुभव के आधार पर, पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का नमूना ले सकते हैं, देख सकते हैं कि फसलें कैसे उगाई जाती हैं, कपड़ा बुनाई में भाग लेते हैं, लोक कलाओं का अभ्यास और प्रदर्शन करते हैं, और समुदाय के भीतर रहते हुए प्रकृति की राह पर चलते हैं।

## स्थायी पर्यटन

* इस ग्रामीण धक्का का ध्यान स्थिरता है, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से बचना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना।
* इसके बजाय, एक अद्वितीय जैविक अनुभव प्रदान करने के लिए स्थानीय संसाधनों और समुदायों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
* इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
* केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय एक बजट तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसमें जिला स्तर पर कुछ प्रशिक्षण मॉड्यूल 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित हैं, और अन्य पहलू 60% केंद्र और 40% राज्य वित्तपोषित हैं।
* जबकि वैश्विक ग्रामीण पर्यटन रुझानों पर समेकित डेटा की कमी है, यूएस-आधारित मार्केट रिसर्च फर्म ग्रैंड व्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2022 से 2030 तक अकेले एग्रीटूरिज्म 11.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में विकसित होगा ।

## ग्राम समूह

* ग्रामीण गंतव्यों को बढ़ावा देने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करीब पांच से सात गांवों के समूहों की पहचान करना होगा।
* एक क्लस्टर लंबी दूरी से अलग-अलग गांवों की ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की तुलना में अधिक पर्यटक आकर्षण प्रदान करेगा।
* शिल्प बाज़ारों के माध्यम से गाँवों के समूह के स्थानीय उत्पादों के विपणन में भी सहायता कर सकता है ।
* केंद्रीय नोडल एजेंसी ने राज्यों को पर्यटन विकास के लिए उच्च क्षमता वाले व्यक्तिगत और गांवों के समूह दोनों की पहचान करने के लिए कहा है।
* सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूर्बन क्लस्टर्स पर भी विचार कर रही है, जहां विकास की संभावना वाले गांवों के समूह की पहचान की जाती है।

## ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

* **मनरेगा के तहत स्थलों का निर्माण**
* ग्रामीण विकास मंत्रालय को पर्यटन बुनियादी ढांचे के लिए मनरेगा के तहत स्थलों के निर्माण की संभावना तलाशने के लिए कहा गया है।
* जैविक कृषि क्षेत्रों की खोज
* सरकार परम्परागत के तहत विकसित जैविक कृषि क्षेत्रों की खोज कर रही है कृषि विकास ग्रामीण पर्यटन स्थलों के रूप में विकास के लिए योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन (एमओवीसीडी-एनईआर)।
* **राज्य मूल्यांकन और रैंकिंग मानदंड:**
* पर्यटन मंत्रालय भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य मूल्यांकन और रैंकिंग मानदंड शुरू करने पर काम कर रहा है।
* **स्वदेश दर्शन योजना:**
* स्वदेश \_ दर्शन योजना" विषय-आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास की स्थापना करना चाहती है।
* **देखो अपना देश :**
* “ देखो अपना देश ” योजना, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को विदेशों के बजाय घरेलू यात्रा के लिए राजी करना है।
* **जीवंत ग्राम कार्यक्रम:**
* सीमावर्ती बस्तियों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर्यटन के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा।
* **अमृत धरोहर योजना:**
* इस कार्यक्रम की शुरुआत का उद्देश्य संरक्षण और संरक्षण है।
* यह क्षेत्र की आर्द्रभूमि का सर्वोत्तम उपयोग करेगा, जैव विविधता को बढ़ावा देगा, और पारिस्थितिक पर्यटन विकल्पों को बढ़ावा देगा, ये सभी पर्यटन को बढ़ाएंगे।
* **एकता मॉल लॉन्च किया जाएगा:**
* प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर यूनिटी मॉल की स्थापना से केंद्र सरकार को स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहायता करने में मदद मिलेगी।
* इन मॉल में जीआई आइटम और राज्य के अनूठे ओडीओ पीएस (एक जिला, एक उत्पाद) की सुविधा होगी।
* **इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा:**
* केंद्रीय बजट में 50 और हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रोम और अन्य लैंडिंग क्षेत्रों के विकास का भी उल्लेख किया गया है।
* साथ ही रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए मिले हैं । कनेक्टिविटी में सुधार के साथ पर्यटन अनिवार्य रूप से बढ़ेगा और वहां पहुंचने के लिए और विकल्प होंगे।

## निष्कर्ष:

* बुनियादी ढांचे में निवेश, आकर्षणों तक पहुंच और स्थानीय समुदायों के साथ ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए शुरू किए गए प्रयासों में से एक है।
* इसके परिणामस्‍वरूप रोजगार सृजित होंगे और सांस्‍कृतिक विरासत संरक्षित रहेगी, जो पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगी।
* ग्रामीण पर्यटन न केवल स्थानीय कला और शिल्प को पुनर्जीवित कर सकता है और व्यवहार्य पारंपरिक व्यवसायों को विस्थापित होने से रोक सकता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्विकास और ग्रामीण जीवन को फिर से जीवंत करने में भी मदद करेगा।

**प्रश्न:**7 भारत में संसद के सदस्य की अयोग्यता के लिए आधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और अयोग्य विशेषताओं वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

# एक राजनेता की अयोग्यता का मामला - समसामयिकी लेख

* हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने कवारत्ती जिला और सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दिए गए फैसले को निलंबित कर दिया , जिसमें लक्षद्वीप के तत्कालीन मौजूदा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पीपी मोहम्मद फैजल को सजा सुनाई गई थी । 10 साल जेल में रहने के बाद उनकी अयोग्यता पर दिलचस्प सवाल खड़े किए हैं।

## पृष्ठभूमि

* श्री फैज़ल को कवारत्ती सत्र अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया था और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
* 13 जनवरी को, लोकसभा ने घोषणा की कि उन्हें सजा की तारीख से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
* 18 जनवरी को, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 27 फरवरी को उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-चुनाव की तारीख तय की, जिसकी औपचारिक अधिसूचना 31 जनवरी को जारी की जाएगी।
* श्री फैज़ल ने अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपील की, जिसे उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को निलंबित कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपील के निस्तारण तक उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया।
* श्री फैजल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ईसीआई की घोषणा को चुनौती दी और 30 जनवरी को ईसीआई ने कहा कि वह चुनाव को टाल रहा है।

## अयोग्यता का प्रावधान

* **अनुच्छेद 102:**
* अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है, जो निर्दिष्ट करता है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
* इनमें लाभ का पद धारण करना , अस्वस्थ मस्तिष्क या दिवालिया होना, या भारत का नागरिक नहीं होना शामिल है।
* यह संसद को अयोग्यता की शर्तों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने के लिए भी अधिकृत करता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए समान प्रावधान हैं।
* **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:**
* इस अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । व्यक्ति कारावास की अवधि और एक और छह साल के लिए अयोग्य है।
* **अपवाद :**
* मौजूदा सदस्यों के लिए एक अपवाद है; उन्हें अपील करने के लिए सजा की तारीख से तीन महीने की अवधि प्रदान की गई है; अपील का निर्णय होने तक अयोग्यता लागू नहीं होगी ।

## अयोग्यता से संबंधित निर्णय

* **प्रभाकरन बनाम पी. जयराजन (2005):**
* चुनावों और मौजूदा सदस्यों के लिए उम्मीदवारों के अलग-अलग व्यवहार को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत चुनौती दी गई थी।
* अदालत ने फैसला किया कि एक प्रतियोगी और मौजूदा सदस्य को अयोग्य घोषित करने के परिणाम अलग-अलग थे।
* अदालत ने विचार किया कि क्या अयोग्य उम्मीदवार के मामले में, जिसे बाद में बरी कर दिया गया है, अयोग्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव से हटा दिया जाएगा।
* इसने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए चुनाव के परिणामों को रद्द करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, अयोग्यता को हटाना भविष्य के चुनावों के लिए संभावित होगा।
* **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामला :**
* यह कहा गया था कि अनुच्छेद 102 संसद को "संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए" किसी व्यक्ति की अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
* फैसले में अनुच्छेद 101 का हवाला दिया गया, जिसमें प्रावधान है कि अगर एक सांसद को अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, तो "उसकी सीट खाली हो जाएगी "।
* अयोग्यता स्वचालित थी और अनुच्छेद 102 की शर्तों को पूरा करने पर तत्काल प्रभाव पड़ता था ।

## अगर दोषसिद्धि निलंबित कर दी जाती है तो क्या होता है?

* अगर सजा निलंबित कर दी जाती है, तो अपील का फैसला होने तक अयोग्यता को हटाया जा सकता है।
* नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में देखा गया था , जिन्हें सांसद रहते हुए दोषी ठहराया गया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
* उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया लेकिन चुनाव लड़ना चाहते थे, और अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील की।
* सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसने अपील का फैसला होने तक अयोग्यता को हटा दिया । इस फैसले ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी।

## अब क्या होता है?

* लक्षद्वीप सीट को खाली घोषित किया गया था लेकिन ईसीआई ने स्थगन आदेश के बाद उपचुनाव टालने की घोषणा की। लोकसभा ने सीट को खाली रखा है और अभी तक सांसद को बहाल नहीं किया है।
* महंगे चुनाव से बचने के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। सवाल यह है कि क्या अयोग्यता को हटाने को बैक-डेट किया जा सकता है जैसे कि ऐसा कभी नहीं हुआ और चुनाव टाल दिया गया। अथवा क्या स्थगन आदेश की तिथि से ही निरर्हता हटा दी जाती है, और इसलिए रिक्त स्थान को उपचुनाव के माध्यम से ही भरा जा सकता है।
* यह पहेली इसलिए पैदा होती है क्योंकि लिली थॉमस के फैसले में अयोग्य होने पर सीट को तुरंत खाली करने की आवश्यकता होती है, जबकि केरल उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सांसद अपील का फैसला होने तक सीट बरकरार रखे।
* उत्तर का भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए भी निहितार्थ होगा।

**प्रश्न:**8 भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक नीति उपकरण के रूप में उत्सर्जन व्यापार योजना (ईटीएस) को लागू करने के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें।

# उत्सर्जन व्यापार योजना अधिसूचित करने के अंतिम चरण में केंद्र - समसामयिकी लेख

* पिछले साल दिसंबर में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद भारत उत्सर्जन व्यापार योजना (ईटीएस) को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

## योजना के बारे में:

* इस योजना के लिए प्रदूषणकारी उद्योगों को कुछ ऊर्जा दक्षता मानकों को पूरा करने की आवश्यकता है और उन्हें सुधारों का व्यापार करने की अनुमति देता है।
* भारत सरकार निर्दिष्ट करेगी कि किन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और वे लक्ष्य जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है, जिसकी घोषणा जून 2023 तक की जाएगी।
* ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जो ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक निकाय है, योजना का नोडल समन्वयक होगा।

## ऊर्जा दक्षता लक्ष्य और ट्रेडिंग क्रेडिट:

* ईटीएस एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऊर्जा दक्षता लक्ष्य देगा।
* लक्ष्य से अधिक होने वाली कंपनियों को क्रेडिट या प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे जिन्हें वे या तो बेच सकते हैं या उन कंपनियों को बैंक कर सकते हैं जो लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं।
* यूरोपीय संघ और कोरिया में उत्सर्जन व्यापार योजनाएं पहले से मौजूद हैं ।
* बीईई पहले से ही 2015 से " परफॉर्म, अचीव, ट्रेड " नामक एक समान योजना लागू कर रहा है।
* 13 क्षेत्रों में 1,078 उद्योगों को शामिल किया गया है जो निश्चित लक्ष्य से अधिक होने पर ऊर्जा सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे हैं।
* हालांकि, नए ईटीएस के तहत उत्पन्न क्रेडिट कंपनियों को दक्षता मानदंडों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में अधिक निवेश करने के लिए मजबूर करेगा।

## उत्सर्जन व्यापार योजनाओं के लिए एक अलग दृष्टिकोण:

* अन्य देशों से भारतीय ईटीएस में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन में पूर्ण रूप से कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी।
* भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता (जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन) को 45% (2005 के स्तर के) तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
* भारतीय ईटीएस के तहत कंपनियां अधिक कुशल होते हुए भी उत्पादन बढ़ा सकती हैं और अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर सकती हैं ।
* जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता है , जो भारत के लिए अनिवार्य नहीं है।

## ट्रेडिंग के लिए पात्र ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण गतिविधियां

* भारतीय कार्बन बाजारों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कई गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है जो कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए पात्र होंगी।
* इनमें सौर तापीय ऊर्जा, अपतटीय पवन, हरित हाइड्रोजन, संपीडित बायोगैस और संग्रहीत नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।

## गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की लागत

* केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 GW बिजली पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिसकी लागत कम से कम ₹2.4 ट्रिलियन होगी।
* विशेषज्ञों ने भारत के लिए अपनी खुद की उत्सर्जन व्यापार योजना संरचना की आवश्यकता पर जोर दिया जो पश्चिमी मॉडलों से सीखते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करे ।

## कार्बन क्रेडिट और उत्सर्जन व्यापार योजनाओं के बीच अंतर:

* कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन व्यापार योजनाओं से अलग योजना है।
* पुरानी योजना में, भारतीय उद्योगों ने कोयला, तेल और गैस के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न करने के लिए सिस्टम स्थापित किया और क्रेडिट का दावा किया जो उत्सर्जन को प्रतिबिंबित करता था जिसे सैद्धांतिक रूप से रोका गया था।
* ये क्रेडिट यूरोपीय संघ में एक्सचेंजों को बेचे गए जहां कंपनियों को ऐसे क्रेडिट के साथ अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करने की आवश्यकता थी।
* कई कंपनियाँ स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बैंक के अपने गठजोड़ को दर्शाने के साथ-साथ उनका व्यापार करने के लिए स्वैच्छिक ऑफ़सेट करती हैं।
* कार्बन क्रेडिट वास्तव में रोके गए उत्सर्जन को दर्शाते हैं, जबकि ईटीएस जैसी योजनाओं से ऊर्जा प्रमाणपत्र उत्सर्जन को रोकने पर सरकारी नियमों के अनुपालन में उद्योग द्वारा निवेश को दर्शाते हैं।

## डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक उपकरण के रूप में घरेलू ईटीएस

* ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के विश्लेषकों ने भारतीय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की घोषणा को " पाथब्रेकिंग " कहा।
* उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय हितधारकों को घरेलू ईटीएस को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के बजाय डीकार्बोनाइजेशन और घरेलू जलवायु वित्त के लिए एक साधन के रूप में देखना चाहिए।

## आगे की राह:

* **नियामक ढांचे को मजबूत बनाना:**
* ईटीएस कार्यान्वयन और निगरानी के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश स्थापित करना।
* गैर-अनुपालन और धोखाधड़ी के लिए दंड को मजबूत करना।
* व्यापार प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
* **भागीदारी को प्रोत्साहित करना:**
* प्रारंभिक गोद लेने और भागीदारी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
* ईटीएस के लाभों के बारे में उद्योग के हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
* जिन कंपनियों को समर्थन की आवश्यकता है उन्हें तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की पेशकश करना ।
* **कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता बढ़ाना:**
* उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्सर्जन व्यापार के लिए कठोर मानक स्थापित करना।
* उत्सर्जन व्यापार प्रक्रिया में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करना
* **बाजार के बुनियादी ढांचे का निर्माण**
* ईटीएस के लिए एक मजबूत बाजार बुनियादी ढांचा विकसित करना जिसमें रजिस्ट्रियां, एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस शामिल हैं।
* ईटीएस में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए वित्तपोषण और तरलता तक पहुंच को सुगम बनाना ।
* उत्सर्जन व्यापार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए नवीन वित्तीय साधनों के विकास का समर्थन करना ।
* **सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
* ETS नीतियों और मानकों को संरेखित करने के लिए अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संवाद और सहयोग में संलग्न होना ।
* ईटीएस कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त और तकनीकी सहायता का लाभ उठाना।
* ETS को लागू करने वाले या ऐसा करने पर विचार कर रहे देशों के बीच ज्ञान-साझाकरण और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देना।

**प्रश्न:** 9 बढ़ते मानव-पशु संघर्षों के प्रमुख कारण और परिणाम क्या हैं? साथ ही, इन मुद्दों के समाधान के लिए कुछ प्रगतिशील उपायों का सुझाव दें। (250 शब्द)

# अधिक पशु, कम वन आवरण - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

* कर्नाटक मानव-पशु संघर्षों में वृद्धि से जूझ रहा है, जिसने वन्यजीवन और वन संरक्षण के मुद्दों को सामने ला दिया है और राज्य की प्रतिक्रिया के बारे में सवाल उठाए हैं।
* इस महीने की शुरुआत में जेनु कुरुबा समुदाय से जुड़े एक 70 वर्षीय बुजुर्ग कोडागु जिले में कुट्टा के पास नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर बाघ के हमले में और उनके 12 वर्षीय पोते की मौत हो गई थी।
* कुछ महीनों के अंतराल में दक्षिण कर्नाटक में मानव-तेंदुए के संघर्ष में चार लोगों की मौत हुई ।

## मुख्य विचार:

* गुब्बी और उनकी टीम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार , कर्नाटक राज्य में तेंदुए की आबादी लगभग 2,500 है।
* मानव-तेंदुआ संघर्ष का 50% से अधिक पांच जिलों- रामनगर , तुमकुरु , मांड्या , मैसूर और हासन में होता है।

## मानव-पशु संघर्ष:

* मानव-वन्यजीव संघर्ष तब होता है जब मानव और वन्य जीवन के बीच मुठभेड़ के नकारात्मक परिणाम होते हैं , जैसे कि संपत्ति, आजीविका और यहां तक कि जीवन की हानि।

## बढ़ते विवाद के कारण:

* जैसे-जैसे मानव आबादी और स्थान की मांग बढ़ती जा रही है , लोग और वन्यजीव तेजी से संसाधनों के लिए परस्पर क्रिया और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हो सकती है।
* जब संरक्षण उपायों के कारण वन्य जीवों की आबादी बढ़ रही थी , तो बफर जोन बनाकर वन आच्छादित क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए था।
* लेकिन कर्नाटक में इसका उलटा हुआ ।
* गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि को मोड़कर सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने से वन या तो सिकुड़ गए हैं ।
* 2020-21 और 2021-22 के बीच, जब मानव-पशु संघर्ष एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, 450 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को खनन, सड़क निर्माण, सिंचाई, पवन चक्कियों और रेलवे लाइनों सहित 39 परियोजनाओं के लिए बदल दिया गया।
* कुल भूमि क्षेत्र 43,356.47 वर्ग किमी या राज्य के भूमि क्षेत्र का 22.61% था।
* यह घटकर 4,0591.97 वर्ग किमी या भूमि क्षेत्र का 21.16% हो गया है।
* राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना का भी विरोध किया है जो हरित क्षेत्र की रक्षा में मदद कर सकता है।

## संघर्ष के परिणाम:

* रक्षात्मक और प्रतिशोधात्मक हत्या अंततः इन प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर सकती है।
* इन मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप न केवल संघर्ष से प्रभावित लोगों और वन्य जीवन दोनों के लिए पीड़ा होती है ; उनके पास एक वैश्विक पहुंच भी हो सकती है , जिसमें सतत विकास एजेंसियों और व्यवसायों जैसे समूहों को इसके अवशिष्ट प्रभाव महसूस हो रहे हैं।
* वन विभाग के अनुसार, 2020-21 के दौरान, जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति से संबंधित 24,740 मामले सामने आए ; मवेशियों की मौत के 3,019 मामले ; और राज्य में 36 लोगों की मौत हुई है ।
* सभी मामलों में कुल मिला कर दिया गया मुआवजा ₹21.64 करोड़ था ।
* 2021-22 में जंगली जानवरों से फसल खराब होने के मामले बढ़कर 31,225 हुए; मारे गए मवेशियों की संख्या 4,052 हो गई; और 40 लोगों की मौत की सूचना मिली थी।
* भुगतान किया गया मुआवजा ₹ 27.4 करोड़ से अधिक है।
* चालू वर्ष में , मुआवजे के रूप में ₹20 करोड़ से अधिक का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। और एक बार लंबित आवेदनों पर कार्रवाई हो जाने के बाद, यह आंकड़ा ₹40 करोड़ को पार करने की उम्मीद है ।
* कीमत , मौतों और फसल की क्षति दोनों के संदर्भ में, जंगल के किनारे और गांवों में रहने वाले लोगों द्वारा वहन की जा रही है।
* वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय समर्थन कम हो सकता है ।
* यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो मानव-वन्यजीव संघर्ष में इन गतिविधियों और संरक्षण को और अधिक व्यापक रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है।

## सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

* राज्य के सरकारी अधिकारियों ने संघर्षों को कम करने के लिए निवारक योजनाओं के बारे में सोचा है।
* इनमें जंगल की सीमाओं से सटे गांवों में रेल की टूटी हुई बाड़, और संघर्ष क्षेत्रों से हाथियों और बाघों को स्थानांतरित करना शामिल है।
* दो या तीन अलग-अलग बाड़े या बचाव केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है ।
* 250 तेंदुओं को रखने की क्षमता होगी जिन्हें ट्रैंकुलाइज करके संघर्ष क्षेत्रों में पकड़ लिया गया है।
* अकेले अप्रैल 2022 से इस साल जनवरी के बीच कर्नाटक में संघर्ष क्षेत्रों से लगभग 130 तेंदुए पकड़े गए हैं ।

## आगे की राह:

* हालांकि शमन पहल अनिवार्य हैं, कुछ का मानना है कि वे केवल लक्षणों को संबोधित करते हैं न कि कारण को।
* ऐसा इसलिए है क्योंकि संघर्षों में वृद्धि और मानव मौतों में वृद्धि को एक ओर सरकार के संरक्षण उपायों और दूसरी ओर विकास नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम माना जाता है , जो एक दूसरे के विपरीत हैं।
* नतीजतन, पर्यावरण छोटा हो जाता है।
* बफर जोन बनाकर वन आच्छादित क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
* ऐसे क्षेत्र पशु आबादी में वृद्धि को अवशोषित करने के लिए सिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं और पशु प्रवासन के लिए संपर्क प्रदान कर सकते हैं ।
* वृक्षारोपण और भूमि से सटे वन क्षेत्र बफर जोन को बढ़ा और मजबूत कर सकते हैं और संघर्षों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
* यदि ऐसी वन भूमि रूपांतरण नीतियां , जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, को उलटा नहीं किया जाता है , तो संघर्षों को कम करने के लिए शमन उपायों का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा और मानव-पशु संघर्ष भविष्य में और बढ़ेंगे।
* मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, हमें भविष्य में अपने सह-अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए लोगों और वन्यजीवों के बीच संबंधों-और विशेष रूप से प्रत्यक्ष बातचीत-का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

## निष्कर्ष:

* प्रक्रिया में सक्रिय और समान प्रतिभागियों के रूप में प्रभावित समुदायों के साथ प्रणालीगत, संदर्भ-विशिष्ट समाधानों को विकसित करते हुए संघर्ष के गहरे, अंतर्निहित कारणों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने वाले दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता है ।

**प्रश्न:**10 हरित विकास क्या है? सरकार भारत में हरित विकास कैसे सुनिश्चित कर रही है? (250 शब्द)

# बजट द्वारा हरित विकास को ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

* भारत की G20 अध्यक्षता के साथ, सात प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं में से एक के रूप में हरित विकास की पहचान एक स्थायी भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

## हरित विकास क्या है?

* हरित विकास का अर्थ यह सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देना है कि प्राकृतिक संपत्ति संसाधन और पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करती रहे, जिस पर हमारी भलाई निर्भर करती है।
* ऐसा करने के लिए इसे निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करना चाहिए जो निरंतर विकास को सहारा देगा और नए आर्थिक अवसरों को जन्म देगा।

## इसे हासिल करने का लक्ष्य क्या है?

* प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में अधिक दक्षता के लिए प्रोत्साहन बनाकर, अपशिष्ट और ऊर्जा की खपत को कम करके, नवाचार और मूल्य निर्माण के अवसरों को अनलॉक करके, और संसाधनों को उच्चतम मूल्य उपयोग के लिए आवंटित करके उत्पादकता में वृद्धि करना ।
* प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों से सरकारें कैसे निपटती हैं, इस बारे में अधिक पूर्वानुमेयता के माध्यम से निवेशकों का विश्वास बढ़ाना ।
* हरित वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों की मांग को प्रोत्साहित करके नए बाजार खोलना ।
* हरित करों के माध्यम से और पर्यावरणीय रूप से हानिकारक सब्सिडी के उन्मूलन के माध्यम से राजस्व जुटाकर राजकोषीय समेकन में योगदान करना। ये उपाय पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, या अन्य गरीब-समर्थक निवेश जैसे क्षेत्रों में गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के लिए संसाधन उत्पन्न करने या मुक्त करने में भी मदद कर सकते हैं।
* संसाधन बाधाओं के साथ-साथ हानिकारक और संभावित अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय प्रभावों के कारण विकास के लिए नकारात्मक झटके के जोखिम को कम करना ।

## सरकार हरित विकास कैसे सुनिश्चित कर रही है?

* वित्त मंत्री ने चार अवसरों के बीच "हरित विकास" को सूचीबद्ध किया जो देश की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 तक भारत के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है।
* अन्य तीन हैं:
* महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण,
* एमएसएमई क्षेत्र के साथ पारंपरिक कारीगरों को एकीकृत करना, और
* पर्यटन।
* **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी):**
* सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम कर देगा । वर्ष 2030, और गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50% स्रोत समान समय सीमा।
* **पीएम प्रणाम (PRANAM):**
* पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम , वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी ।
* **गोबरधन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन):**
* गोबर्धन के तहत लगभग 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट लॉन्च किए जाएंगे (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन ) परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए।
* 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे।
* आने वाले समय में, प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% सीबीजी अधिदेश पेश किया जाएगा।
* बायोमास के संग्रहण एवं जैव खाद के वितरण हेतु समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
* **मिष्टी :**
* यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) और क्षतिपूरक वनीकरण कोष के बीच अभिसरण के माध्यम से समुद्र तट के किनारे और नमक के मैदानों पर मैंग्रोव वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
* **अमृत धारोहर :**
* अमृत के माध्यम से स्थानीय समुदायों की संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देगी धरोहर, एक योजना जो अगले तीन वर्षों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए लागू की जाएगी।
* वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ पीपीपी मोड के माध्यम से तटीय शिपिंग को परिवहन के एक ऊर्जा कुशल मोड के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
* **कृषि त्वरक निधि**
* बजट में घोषित कृषि त्वरक कोष उद्यमियों को नवाचार चलाने के लिए महत्वपूर्ण धन मुहैया कराएगा।
* **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम**
* ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम प्रोत्साहित करने के लिए बजट में रेखांकित किया गया है लोगों, संगठनों और स्थानीय निकायों के व्यवहार में बदलाव उत्साहजनक है।
* **ऊर्जा संरक्षण विधेयक**
* ऊर्जा संरक्षण विधेयक एक घरेलू कार्बन बाजार के निर्माण की कल्पना करता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार के प्रत्याशित पुनरुद्धार के साथ मिलकर, सरकार न केवल कार्बन ऑफसेट के विश्व के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत के उद्भव को प्रोत्साहित कर सकती है, बल्कि व्यापक मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकती है। उद्योगों को उनकी दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं के लिए।
* **म्युनिसिपल बांड:**
* हरित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहरों के लिए सफल उपकरण साबित हुए हैं।
* हाल ही में एक अपशिष्ट संयंत्र के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने और इंदौर के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की सफलता इस एवेन्यू के माध्यम से भारत में स्थायी शहरों के निर्माण के लिए हरित वित्तपोषण के वादे को दर्शाती है।

## निष्कर्ष:

* निष्पादन महत्वपूर्ण होगा, पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में।
* 2023 तक 5,000 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों को प्राप्त करने के लिए 2018 में घोषित सतत परिवहन के लिए सतत विकल्प (SATAT) योजना, अब तक लक्ष्य का केवल 1 प्रतिशत ही पूरा कर पाई है ।
* 175GW नवीकरणीय ऊर्जा के 2022 के लक्ष्य का लगभग 60 प्रतिशत ही वितरित किया गया था।
* केंद्रीय बजट हरित या जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने वाली परियोजनाओं और पहलों के लिए वित्तीय आवंटन को दर्शाता है।
* यह फोकस महत्वपूर्ण है, इसे इस समझ के भीतर स्थित करने की आवश्यकता है कि ये वित्त, एक बार आवंटित होने पर नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण या हरित निर्माण या रैखिक बुनियादी ढांचे सहित विशिष्ट परियोजनाओं में आवश्यक रूप से परिवर्तित हो जाएंगे।
* इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय निवेश के लिए पारिस्थितिक सावधानियों और सामाजिक लागत आकलन पर सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है जो परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन दोनों में मायावी हैं।

**प्रश्न:**11 यूएस-भारत साझेदारी वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक मानचित्र को महत्वपूर्ण रूप से पुनर्परिभाषित कर सकती है । वरीयता कार्यक्रम की सामान्यीकृत प्रणाली में भारत को बहाल करना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होगा। टिप्पणी करें। (250 शब्द)

# भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों का पुनर्निर्माण - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

* अमेरिका चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास कर रहा है, और भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी पहलों के साथ समान रणनीति अपना रहा है।
* यह भारत को उभरती आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है। दोनों देशों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राजकीय यात्राओं की बढ़ती संख्या के माध्यम से भारत और अमेरिका दोनों इस मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं।

## पृष्ठभूमि:

* अमेरिकी वायु सेना ने हाल ही में एक गुब्बारे को मार गिराया , यह आरोप लगाते हुए कि यह एक चीनी जासूसी उपकरण था। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना दिया है।
* इसके अलावा, उनके व्यापार संबंधों को हाल के वर्षों में व्यापार घाटे पर विवाद, बौद्धिक संपदा की चोरी और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित कई मुद्दों द्वारा चुनौती दी गई है।
* रूस-यूक्रेन युद्ध ने मामलों को बदतर बना दिया है, विकसित राष्ट्रों ने पुरानी औद्योगिक नीति प्लेबुक को उठाया है।
* रीगन-थैचर क्रांति और वाशिंगटन सहमति की स्थापना के बाद के दशकों तक, आर्थिक रूढ़िवादिता उन नीतियों के खिलाफ थी जिसमें निर्णयों को बाजार पर छोड़ने के बजाय "विजेताओं को चुनना" शामिल था ।
* हालांकि, वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के अपने प्रयासों में, अमेरिका ने कानून के दो महत्वपूर्ण टुकड़े बनाए हैं - चिप्स और विज्ञान अधिनियम और मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम ।
* चिप्स और विज्ञान अधिनियम का उद्देश्य घरेलू अर्धचालक उद्योग का निर्माण करना और चीन पर अमेरिका के वैज्ञानिक वर्चस्व को आगे बढ़ाना है, मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा संचरण को प्रोत्साहित करना है।
* अमेरिका चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। यह भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। भारत और अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं ।

## भारत-अमेरिका व्यापार संबंध:

* उदारीकरण के बाद भारत-अमेरिका व्यापार में सुधार के बावजूद, कई बाधाओं ने एक व्यापक व्यापार समझौते को रोका है।
* दोनों देश चीनी आयात पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कृषि, श्रम मानकों, जलवायु और मानवाधिकारों पर उनके अलग-अलग विचार हैं ।
* ये वर्तमान इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) में परिलक्षित होते हैं, जो व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा (डिकार्बोनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर), टैक्स और भ्रष्टाचार विरोधी पर क्षेत्रीय सहयोग बनाने की कोशिश करता है ।
* आपूर्ति श्रृंखला और स्वच्छ ऊर्जा विशेष रूप से आशाजनक क्षेत्र हैं, दोनों देशों में हाल ही में नीतिगत विकास, जैसे कि हरित हाइड्रोजन।
* ये पूरक पहलों के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं जो मजबूत वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने में मदद कर सकते हैं, हालांकि, भारत अभी तक इस ढांचे के व्यापार घटक में शामिल नहीं हुआ है।
* व्यापार प्रथाओं पर चिंताओं और अमेरिकी कंपनियों को न्यायसंगत और उचित बाजार पहुंच प्रदान करने में विफलता का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत को जीएसपी कार्यक्रम से हटा दिया।
* **सर्विस सेक्टरः** अमेरिका चाहता है भारतीय शिक्षा और बीमा बाजारों तक अधिक पहुंच, जबकि भारत अधिक अमेरिकी श्रम पहुंच चाहता है। इसलिए, मर्चेंडाइज खंड से अधिक, सेवा खंड में भारत और अमेरिका के बीच अधिक पूरकताएं हैं।
* श्रम और पर्यावरण मानक संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत रहे हैं। जबकि अमेरिका का मानना है कि वैश्विक कल्याण की सुरक्षा के लिए इन मानकों को संरेखित करना महत्वपूर्ण है, भारत की सीमित क्षमता ने इसे इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से रोक दिया है।

## आगे की राह:

* भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के निर्माण के लिए बहुत सारे जमीनी कार्य किए जाने चाहिए। पहले कदम के रूप में, दोनों देश निम्नलिखित पर काम कर सकते हैं:
* वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) में भारत की बहाली ।
* व्यापक मुक्त व्यापार वार्ताओं के ढांचे के बाहर सेवा व्यापार पर बातचीत शुरू करें।
* श्रम और पर्यावरण मानकों पर बौद्धिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान शुरू करें।
* जीएसपी ने अमेरिका को भारतीय निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद की। वास्तव में, भारत जीएसपी प्रणाली का सबसे बड़ा लाभार्थी था।
* भारत को फिर से शामिल करना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होगा।
* दोनों देशों के लिए सेवा व्यापार की पेशकश की पूरकता को देखते हुए, एक स्टैंडअलोन सेवा समझौता दोनों देशों के लिए एक सौदे को अंतिम रूप देने का एक त्वरित अवसर प्रदान कर सकता है।
* उन्नत गिफ्ट सिटी में अमेरिकी निवेश और यूपीआई और रुपे जैसे भारत के फिनटेक नवाचारों का अमेरिका में विस्तार जैसी कई "लचीले फल" संभावनाएं हैं ।
* व्यापक व्यापार समझौते के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की चल रही बातचीत में श्रम और पर्यावरण मानक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं।
* इसलिए, भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इन मानकों पर चर्चा करने और क्रॉस-कंट्री तुलना करने के लिए विशेषज्ञों और अनुसंधान और शैक्षणिक समुदाय को शामिल करे ।

## निष्कर्ष:

* वैश्विक व्यापार का भविष्य ब्लॉकों के बीच विभाजन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका और चीन अग्रणी हैं। यह उम्मीद की जाती है कि एक ब्लॉक के भीतर मुक्त व्यापार मौजूद रहेगा, लेकिन ब्लॉकों के बीच व्यापार सीमित रहेगा।
* अमेरिका के प्रयासों का विकासशील देशों में औद्योगीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
* इसलिए, वार्ता में त्वरित प्रगति का प्रदर्शन अमेरिका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी में वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है

**प्रश्न:**12 लोकतंत्र में खुली और मजबूत चर्चा की आवश्यकता के साथ संसदीय अनुशासन की आवश्यकता किस हद तक संघर्ष करती है? चर्चा करें।

# अनुशासन और चर्चा: जगदीप धनखड़ द्वारा विशेषाधिकार समिति को निर्देश - समसामयिकी लेख

* भारतीय संसद में हाल के घटनाक्रमों ने अनुशासन और जवाबदेही के बीच संतुलन के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

## हाल के मुद्दे:

* **विशेषाधिकार समिति को निर्देश:**
* राज्यसभा के सभापति ने विशेषाधिकार समिति को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान संसद के 12 विपक्षी सदस्यों के " उच्छृंखल आचरण " की जांच करने का निर्देश दिया।
* अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों की भूमिका पर सवाल उठाता है ।
* **कार्यवाही की रिकॉर्डिंग:**
* कथित रूप से अपने मोबाइल फोन पर कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए कांग्रेस सांसद के निलंबन के कारण उचित प्रक्रिया की आलोचना हुई है।
* कांग्रेस ने तर्क दिया है कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उचित नोटिस नहीं दिया गया था।
* यह संसद में अनुशासनात्मक कार्रवाई की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में चिंता पैदा करता है।
* **व्यवधान और निष्काषित किये गए भाषण:**
* राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, राज्यसभा के सभापति ने बार-बार कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण को बाधित किया, जिससे भाषण के छह हिस्से रिकॉर्ड से बाहर हो गए।
* इससे विपक्ष की संसद में अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता और संसदीय कार्यवाही को विनियमित करने में अध्यक्ष की भूमिका के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं ।

## संसदीय विशेषाधिकार

* संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो संसद सदस्यों को उत्पीड़न या अभियोजन के डर के बिना प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाता है।
* क्रमशः संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 105 और 194 के तहत भारतीय संविधान में निहित हैं ।
* इन अनुच्छेदों के तहत, संसद और विधान सभाओं के सदस्यों को सदनों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सदनों के सत्र के दौरान गिरफ्तारी या निरोध से मुक्त होने का अधिकार, और कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार सहित कुछ विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है।
* ये विशेषाधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं कि सदस्य भय या पक्षपात के बिना अपने कार्यों को कर सकें और सदनों की गरिमा और अखंडता की रक्षा कर सकें।
* हालांकि, ये विशेषाधिकार पूर्ण नहीं हैं, और इन्हें सदनों के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए ।

## विशेषाधिकार समिति

* संसद का प्रत्येक सदन और इसकी समितियाँ सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्य व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेते हैं, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते।
* इस समिति में अध्यक्ष (राज्यसभा के मामले में अध्यक्ष) द्वारा नामित 15 सदस्य (राज्यसभा के मामले में 10 सदस्य) शामिल हैं।
* लोकसभा में, अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति के प्रमुख को नामित करता है ।
* राज्य सभा में, उपसभापति विशेषाधिकारों की समिति का प्रमुख होता है ।
* सभा द्वारा या अध्यक्ष/सभापति द्वारा सदन या उसकी किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक प्रश्न की जांच करना है ।
* यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में निर्धारित करता है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन शामिल है और अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त सिफारिशें करता है।

## क्या किया जाने की जरूरत है?

* **संसदीय मानदंडों और सिद्धांतों को बनाए रखें:**
* सरकार को संसदीय मानदंडों और सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए, जो सदन में स्वस्थ और रचनात्मक चर्चा और बहस सुनिश्चित करते हैं।
* संसदीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और बिना पक्षपात के निर्वहन करना चाहिए।
* **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें**
* सरकार को संसद के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए, जो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
* उसे विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से समाधान करना चाहिए, बिना किसी भ्रम या अपवंचन के।
* संसद सदस्य द्वारा की गई किसी भी धारणा या बयान की प्रामाणिकता को सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है।
* **जवाबदेही मांगने पर विपक्ष को दंडित करने से बचें**
* विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार से सवाल पूछे और जवाबदेही मांगने के लिए उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए ।
* सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने से बचे या कठिन सवालों के जवाब देने से बचे।
* **नियत प्रक्रिया का पालन करें**
* संसदीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को संसद सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते समय उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
* संसद सदस्यों को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।
* **रचनात्मक चर्चाओं और बहसों को बढ़ावा देना**
* संसदीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को सदन में रचनात्मक चर्चाओं और बहसों को बढ़ावा देना चाहिए।
* उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद के सभी सदस्य, उनकी राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना, स्वतंत्र रूप से और प्रतिशोध के डर के बिना अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हों।
* सरकार को विपक्ष से रचनात्मक आलोचना और सुझावों के लिए खुला होना चाहिए, जो शासन और नीति निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है ।

**प्रश्न:**13 न्यू स्टार्ट क्या है? मॉस्को द्वारा न्यू स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने के प्रभाव पर चर्चा करें। (250 शब्द

# रूस ने न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित किया - समसामयिकी लेख

## प्रसंग:

* रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में घोषणा की कि मास्को न्यू स्टार्ट संधि - संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है।

## न्यू स्टार्ट क्या है?

* START नाम मूल "स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी" से आया है, जिसे START-I के नाम से जाना जाता है, जिसे 1991 में अमेरिका और तत्कालीन USSR के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, और 1994 में लागू हुआ।
* START-I, जिसने परमाणु वारहेड्स और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) की संख्या को सीमित कर दिया था, जिसे प्रत्येक पक्ष क्रमशः 6,000 और 1,600 पर तैनात कर सकता था, 2009 में समाप्त हो गया , और पहले सामरिक आक्रामक कटौती संधि (SORT) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, (जिसे मॉस्को की संधि के नाम से भी जाना जाता है), और बाद में न्यू स्टार्ट संधि द्वारा जाना गया।
* न्यू स्टार्ट, आधिकारिक तौर पर, "संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों की और कमी और सीमा के उपायों पर संधि", 5 फरवरी, 2011 को लागू हुई, और अंतरमहाद्वीपीय- रेंज परमाणु हथियार।
* दोनों देशों को 5 फरवरी, 2018 तक सामरिक आक्रामक हथियारों पर संधि की केंद्रीय सीमाओं को पूरा करना था, और फिर संधि के लागू रहने की अवधि के लिए उन सीमाओं के भीतर रहना था।
* अमेरिका और रूस संघ बाद में 4 फरवरी, 2026 तक संधि का विस्तार करने पर सहमत हुए।

## New START ने दोनों देशों पर क्या सीमाएँ बनायीं?

* संधि की केंद्रीय सीमाएँ जो अमेरिका और रूस ने 5 फरवरी, 2018 तक पूरी कीं और तब से पालन कर रहे हैं:
* 700 तैनात अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम),
* पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें (एसएलबीएम) तैनात कीं, और परमाणु हथियारों से लैस भारी बमवर्षकों को तैनात किया;
* तैनात किए गए आईसीबीएम पर 1,550 परमाणु हथियार, एसएलबीएम तैनात किए गए, और परमाणु हथियारों से लैस भारी बमवर्षकों को तैनात किया गया (प्रत्येक ऐसे भारी बमवर्षक को इस सीमा की ओर एक वारहेड के रूप में गिना जाता है);
* 800 तैनात और गैर-तैनात ICBM लांचर , SLBM लॉन्चर और परमाणु आयुध से लैस भारी बमवर्षक।

## अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम)

* एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ( ICBM ) 5,500 किलोमीटर (3,400 मील) से अधिक की रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार वितरण (एक या अधिक थर्मोन्यूक्लियर वारहेड देने ) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
* पारंपरिक, रासायनिक और जैविक हथियारों को भी अलग-अलग प्रभावशीलता के साथ वितरित किया जा सकता है, लेकिन आईसीबीएम पर कभी भी तैनात नहीं किया गया है।
* अधिकांश आधुनिक डिज़ाइन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली-टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (MIRVs) का समर्थन करते हैं, जिससे एक मिसाइल को कई वॉरहेड ले जाने की अनुमति मिलती है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग लक्ष्य पर वार कर सकता है।
* रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल और उत्तर कोरिया ही ऐसे देश हैं जो आईसीबीएम के संचालन के लिए जाने जाते हैं।

## पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम)

* एक पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पनडुब्बियों से प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
* आधुनिक वेरिएंट आमतौर पर कई स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य रीएंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक परमाणु वारहेड होता है और एक लॉन्च मिसाइल को कई लक्ष्यों को मारने की अनुमति देता है।
* सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलों से अलग तरीके से काम करती हैं।
* 5,500किलोमीटर (3,000 एनएमआई ) से अधिक की सीमा के साथ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) से निकटता से संबंधित हैं, और कई मामलों में एसएलबीएम और आईसीबीएम हथियारों के एक ही परिवार का हिस्सा हो सकते हैं।

## संधि का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

* केंद्रीय सीमाओं, और सभी संधि दायित्वों के कार्यान्वयन और सत्यापन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ, संधि की शर्तों का हिस्सा हैं।
* ये प्रक्रियाएँ रणनीतिक आक्रामक हथियारों के रूपांतरण और उन्मूलन, संधि-आवश्यक जानकारी के एक डेटाबेस की स्थापना और संचालन, पारदर्शिता के उपाय, सत्यापन के राष्ट्रीय तकनीकी साधनों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता, टेलीमेट्रिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, संचालन को नियंत्रित करती हैं। -साइट निरीक्षण गतिविधियों, और द्विपक्षीय सलाहकार आयोग (बीसीसी) के संचालन।
* संधि यूएस और रूसी निरीक्षण टीमों के लिए प्रति वर्ष 18 ऑन-साइट निरीक्षण प्रदान करती है।
* टाइप वन निरीक्षण तैनात और गैर-तैनात सामरिक प्रणालियों (प्रति वर्ष 10 तक) वाली साइटों पर ध्यान केंद्रित करता है, और टाइप टू निरीक्षण केवल गैर-तैनात रणनीतिक प्रणालियों (प्रति वर्ष 8 तक) वाली साइटों पर ध्यान केंद्रित करता है।
* 1 फरवरी, 2023 तक न्यू स्टार्ट संधि के लागू होने के बाद से, दोनों पक्षों ने 328 ऑन-साइट निरीक्षण किए हैं, 25,311 सूचनाओं का आदान-प्रदान किया है, द्विपक्षीय सलाहकार आयोग की 19 बैठकें आयोजित की हैं, और रणनीतिक आक्रामक हथियारों पर 42 द्विवार्षिक डेटा आदान-प्रदान किया है।

## अनुपालन पर नवीनतम स्थिति क्या है?

* स्टेट डिपार्टमेंट ने इस साल जनवरी में कांग्रेस को बताया कि रूस न्यू START का अनुपालन नहीं कर रहा था, केवल दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण संधि शेष थी, जिससे उनके संबंधों में स्थिरता का स्रोत खतरे में पड़ गया।
* निरीक्षण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने से रूस का इनकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संधि के तहत महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है और अमेरिका-रूसी परमाणु हथियार नियंत्रण की व्यवहार्यता को खतरा पैदा करता है।
* संधि-अनिवार्य समयरेखा के अनुसार द्विपक्षीय सलाहकार आयोग के सत्र को बुलाने के लिए रूस न्यू START संधि दायित्व का पालन करने में भी विफल रहा है।

**प्रश्न:**14 रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बावजूद भारत आर्थिक विकास और सामरिक तटस्थता को बनाए रखने में कैसे कामयाब रहा है, और अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर संभावित प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठा सकता है?

# यूक्रेन युद्ध ने अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया, परन्तु भारत ने अच्छी तरह से प्रबंधन किया - समसामयिकी लेख

* यूक्रेन -रूस युद्ध , जो रूस द्वारा यूक्रेन में दो लाख सैनिकों को भेजने के साथ शुरू हुआ, के परिणामस्वरूप 8,000 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है और अनुमानित आठ मिलियन शरणार्थियों को अपने घरों से भागना पड़ा है।
* जबकि युद्ध ने शुरुआत में आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और विकास को बाधित किया था, भारत ने आर्थिक और सामरिक दृष्टि से काफी अच्छा प्रबंधन किया है।

## युद्ध का वैश्विक प्रभाव:

* यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है ।
* मुद्रास्फीति की दरों में वृद्धि ने विकसित देशों में केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ब्याज दरें और धीमी आर्थिक वृद्धि हो सकती है ।
* कमजोर मुद्राओं , उच्च आयात कीमतों और जीवन यापन की बढ़ती लागतों के संयोजन से कड़ी टक्कर हुई है , जिससे ऋण चुकाना अधिक महंगा हो गया है।
* चूंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योग प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में देरी हुई है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ी हैं।
* भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जिससे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और निवेश प्रवाह में कमी आई है।

## रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव:

* संघर्ष के बावजूद, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध कठोर रूप से नहीं लगाए जा रहे हैं ।
* अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रतिबंधों को इस तरह से लागू करने के इच्छुक नहीं हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचे। नतीजतन, कमोडिटी की कीमतें 2022 के मध्य के अपने उच्चतम स्तर से नीचे हैं।
* कई धातुओं ( टाइटेनियम, एल्युमीनियम और निकेल ), सेमीकंडक्टर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक गैसों, गेहूँ, और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ उर्वरकों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता रहा है , जैसा कि यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने अपनी दिसंबर की रिपोर्ट में उल्लेख किया है।
* वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की परस्पर संबद्धता को देखते हुए, अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रतिबंधों के साथ सावधानी से चल रहे हैं।

## भारत पर प्रभाव:

* **युद्ध के बीच भारत की आर्थिक स्थिति**
* आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक के जनवरी अपडेट के अनुसार , संघर्ष के बावजूद, भारत 2023 और 2024 के लिए क्रमशः 6.1% और 6.8% की अनुमानित विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है ।
* 2023 में रूस की अनुमानित विकास दर 0.3% और 2024 में 2.1% के विपरीत है ।
* अमेरिका और यूरो क्षेत्र के 2023 में क्रमशः 1.4% और 0.7% और 2024 में 1% और 0.6% बढ़ने की उम्मीद है।
* **रूस का रियायती तेल निर्यात:**
* 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत कैप का सामना करना पड़ रहा है , जिससे रूस अपने तेल को भारी छूट पर बेच रहा है , चीन और भारत युद्ध की शुरुआत के बाद से प्रमुख खरीदार के रूप में उभर रहे हैं।
* भारत अब रूस से प्रतिदिन 12 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है, जो एक साल पहले की तुलना में 33 गुना अधिक है।
* चीन, अमेरिका और यूएई के बाद रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा आयात भागीदार बनकर उभरा है, वित्त वर्ष 2023 के अप्रैल-जनवरी के लिए $37.2 बिलियन के ईंधन-चालित आयात के साथ, पिछले वर्ष की तुलना में 384% की वृद्धि हुई है ।
* एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान रूस से इस्पात का आयात मात्रा के लिहाज से पांच गुना बढ़ा है ।
* **महंगाई :**
* संघर्ष ने कच्चे तेल सहित वैश्विक कमोडिटी की कीमतों को कम किया है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली है।
* हालाँकि, संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भी पैदा किया है, जिसके कारण भारतीय फर्मों के लिए उच्च इनपुट लागतें बढ़ी हैं , जिससे मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ा है।
* **पूंजी प्रवाह:**
* संघर्ष ने निवेशकों के बीच सुरक्षा को प्रमुखता दी है, जिससे भारत में पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है।

## व्यापार के डी-डॉलरीकरण के लिए भारत की आवश्यकता:

* भारत को व्यापार के "डी-डॉलरीकरण" के बारे में गंभीर होना चाहिए, जो रूस के संबंध में धरातल पर नहीं उतर पाया है। भू-राजनीतिक समीकरणों के परिणामस्वरूप अस्थिरता हो सकती है, जिसे हेज किया जा सकता है।
* भारतीय रिजर्व बैंक सोने के भंडार को बढ़ा सकता है, जो पिछले साल 1 अप्रैल से इस साल 10 फरवरी के बीच 42 अरब डॉलर से अधिक पर स्थिर रहा है । यह भू-राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न अस्थिरता के प्रभाव को कम करेगा।

## निष्कर्ष:

* रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
* हालाँकि, संघर्ष ने भारत के लिए चीन के खिलाफ एक संभावित भागीदार के रूप में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अवसर भी प्रस्तुत किए हैं, विशेष रूप से फार्मा और विशेष रसायन जैसे उद्योगों में।
* संघर्ष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए , भारत को घरेलू उत्पादन बढ़ाने, अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए।
* इसके अतिरिक्त, भारत को अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए और संघर्ष के कूटनीतिक समाधान की तलाश करनी चाहिए।
* एक सक्रिय और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ , भारत रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकता है और एक मजबूत और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है।

**प्रश्न:**15 जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए तनावपूर्ण क्यों है? हम महासागर पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? (250 शब्द)

* **अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण से गहरे समुद्र को कैसे बचाएं - समसामयिकी लेख**

## प्रसंग:

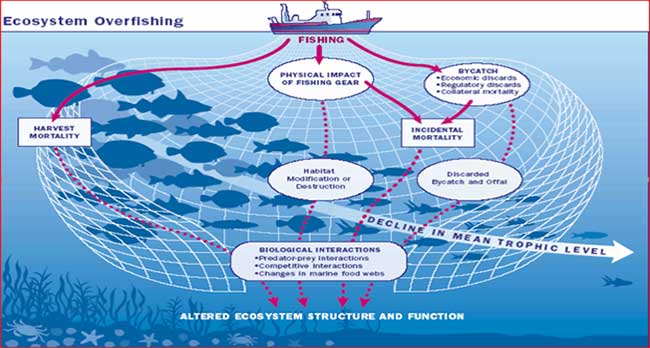
* जबकि गहरे समुद्र दुनिया के महासागरों का 60% से अधिक हिस्सा बनाते हैं , उन्होंने लंबे समय से तटीय जल की तुलना में बहुत कम ध्यान आकर्षित किया है।
* संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संधि में उनकी रक्षा करना चाहता है।

## क्या आप जानते हैं?

* वर्तमान में , 8.16% समुद्री क्षेत्र हैं IUCN के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्तर पर संरक्षित है जिसमें गहरे समुद्रों का 1.44% शामिल है।
* गहरे समुद्री क्षेत्र जो हैं संरक्षित उत्तर पूर्व अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर के हिस्से शामिल हैं , लेकिन क्योंकि संरक्षण समझौते वैश्विक के बजाय क्षेत्रीय होते हैं, वे सभी सरकारों को बाध्य नहीं करते हैं।
* लंदन कन्वेंशन: 1972 के कचरे और अन्य पदार्थों के डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर कन्वेंशन, जिसे लंदन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, मानवीय गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक है।

## मुख्य विचार:

* जब संरक्षण की बात आती है तो दुनिया के महासागरों के विशाल हिस्से अभी भी वाइल्ड वेस्ट हैं।
* मत्स्य पालन, नौवहन, पर्यटन और समुद्र संरक्षण वर्तमान में लगभग 20 संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
* तट से 200 समुद्री मील (370 किलोमीटर) की दूरी पर लागू होते हैं ।
* इसके आगे अंतरराष्ट्रीय जलसीमा शुरू हो जाती है, और अलग-अलग राष्ट्रों के पास कोई शक्ति या अधिकार नहीं है।
* हालाँकि गहरे समुद्र पृथ्वी की सतह के आधे से अधिक और सभी महासागरों का 61% हिस्सा बनाते हैं, केवल 1% अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण में हैं।
* अवैध रूप से मछली पकड़ने, अत्यधिक मछली पकड़ने और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान के अन्य रूपों, जैसे कि गहरे समुद्र में खनन, तेल और गैस ड्रिलिंग, की लगातार निगरानी, ट्रैक या मुकदमा चलाया जा सकता है।
* इसलिए 51 देशों के सरकारी अधिकारी अब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हाई सी ट्रीटी पर बातचीत करना चाहते हैं।



## कैसे महासागर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है?

* महासागर में पर्यावरणीय गिरावट का सबसे बड़ा चालक "अंधाधुंध" मछली पकड़ने से रहा है।
* यह न केवल मछली के स्टॉक को कम करता है बल्कि उनकी आबादी के पुनर्निर्माण की क्षमता को भी मिटा देता है, और कई मछलियां गलती से पकड़ी जाती हैं और बाद में कचरे के रूप में छोड़ दी जाती हैं - तथाकथित बायकैच ।
* अनुमान के मुताबिक, बायकैच का लगभग 40% हिस्सा है दुनिया की वैश्विक वाणिज्यिक पकड़ का ।
* प्रदूषण नुकसान का एक अन्य प्रमुख कारण है, जिसमें प्लास्टिक, सीवेज और अतिरिक्त पोषक तत्व शामिल हैं, जो समुद्र के तल पर बैक्टीरिया के अतिवृद्धि के कारण समुद्र में "मृत क्षेत्र" बनाते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है और अन्य जीवन का दम घुटता है।
* एक ही समय पर, जलवायु परिवर्तन समुद्र के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है - जिससे प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो रहा है और मछलियों को ठंडे पानी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

## एक स्वस्थ समुद्र इंसानों और हमारे ग्रह के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

* समुद्र के संसाधन न केवल तट पर रहने वाले लोगों को, बल्कि दुनिया भर में लगभग 3 अरब लोगों को भी सहारा देते हैं।
* संपूर्ण समुद्री उद्योग का मूल्य $3 ट्रिलियन (€2.8 ट्रिलियन) है - जो कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 5% है।
* समुद्र तट पर्यटकों और मछुआरों के लिए समुद्र केवल महत्वपूर्ण नहीं है।
* हमें टिकाऊ लहर और ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ-साथ वस्तुओं और यहां तक कि दवाओं के उत्पादन के लिए भी इसकी आवश्यकता है।
* मछली खाने वाले समुद्री घोंघे कोनस मैगस के जहर का इस्तेमाल एक प्रभावी दर्दनिवारक विकसित करने के लिए किया जा रहा है।

## महासागरों के लिए जलवायु परिवर्तन तनावपूर्ण क्यों है?

* हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल मात्रा का आधे से अधिक भाग समुद्र में रहने वाले प्राणियों द्वारा बनाया जाता है।
* साथ ही, महासागर हमारे वायुमंडल में वर्तमान में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहीत करते हैं।
* महासागर जितना गर्म होता है, उतना ही कम CO2 वह संग्रहित कर सकता है।
* यह एक दुष्चक्र है: यह जितना गर्म होता है, हमारे महासागर उतने ही कम मौसम की घटनाओं से ग्रह की रक्षा कर सकते हैं।
* यदि तापमान अपनी वर्तमान गति से बढ़ता रहा, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि शंबुक और घोंघे जैसी कई शेलफिश जीवित नहीं रहेंगी।
* यह समुद्र के अम्लीकरण के कारण है: यदि समुद्री जल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो पानी में PH स्तर बदल जाता है।
* यह पूरे जीवमंडल को असंतुलित कर देता है, और पूरे आर्थिक क्षेत्रों को खतरे में डाल सकता है, जैसे सीप और सीपियों का प्रजनन।
* कोयले, तेल और गैस के जलने से वातावरण में बढ़ता तापमान भी समुद्र की धाराओं को बदल देता है क्योंकि पानी गर्म हो जाता है।
* इससे मूंगा जैसे कई जीवों के लिए पहले से ही मृत्यु हो सकता है। कोरल रंगीन शैवाल के साथ सहजीवन में रहते हैं जो उन्हें खिलाने में मदद करते हैं।

## हम महासागर पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

* **मछली पकड़ने की अच्छी प्रथाओं को बढ़ाएँ:**
* खराब मछली पकड़ने की प्रथाओं और प्रसंस्करण के कारण हर साल, हम 10 मिलियन टन मछली फेंक देते हैं - जिससे 4,500 से अधिक स्विमिंग पूल भर सकते हैं।
* इसे रोका जा सकता है, और बदले में सीधे तौर पर हमारे महासागरों पर दबाव कम किया जा सकता है।
* **टिकाऊ सीवेज सिस्टम का निर्माण:**
* वैश्विक अपशिष्ट जल का लगभग 80% वर्तमान में महासागरों में, अनफिल्टर्ड किया जा रहा है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में यह 95% तक भी है।
* यह अपशिष्ट जल महासागरों और तटीय क्षेत्रों को प्रदूषित, दूषित और नष्ट कर देता है।

## आगे की राह:

* अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ महासागरों के विनाश को रोकने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैं।
* तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के संबंध में हाल के वर्षों में कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
* कुछ का पहले से ही पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है; हालांकि, कई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं।
* यूरोपीय संघ प्रजातियों के संरक्षण और ऐतिहासिक 2022 कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वाकांक्षी नई संधि पर जोर दे रहा है।
* इस ऐतिहासिक समझौते का एक हिस्सा 2030 तक दुनिया के 30% हिस्से को सुरक्षा में रखना है।

## निष्कर्ष:

* न्यूयॉर्क में बातचीत की जा रही हाई समुद्र संधि गहरे समुद्र में संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए कानूनी तंत्र बनाकर "अंतराल" भर देगी।
* वास्तविक परीक्षा उन हाई समुद्र संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे अत्यधिक और पूरी तरह से निष्कर्षण गतिविधियों से सुरक्षित हैं।

**प्रश्न:**16 H5N1 वायरस के प्रसार से निपटने में चुनौतियों का उल्लेख करें और भविष्य में तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार के उपायों का सुझाव दें। (250 शब्द)

* **एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए पर्यावरणीय निगरानी का महत्व - समसामयिकी लेख**
* दुनिया की सबसे बड़ी उत्तरी गनेट कॉलोनी , उत्तरी बेरविक, स्कॉटलैंड के तट से दूर एक द्वीप हाल ही में एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) या बर्ड फ्लू द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जिससे ब्रिटेन में हजारों पक्षियों का नुकसान हुआ।

## एवियन इन्फ्लूएंजा:

* एवियन इन्फ्लूएंजा, या बर्ड फ्लू, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है।
* कभी-कभी, वायरस पक्षियों से स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है, जिसे स्पिलओवर कहा जाता है, और शायद ही कभी स्तनधारियों के बीच फैल सकता है।
* एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के कई अलग-अलग उपप्रकार हैं, जिनमें निम्न रोगजनक से लेकर अत्यधिक रोगजनक प्रकार शामिल हैं जो पक्षियों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
* H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा का एक अत्यधिक रोगजनक उपप्रकार है जो पक्षियों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है।
* इस उपप्रकार ने संक्रमित पक्षियों, या दूषित वातावरण के निकट संपर्क के माध्यम से कई मानव संक्रमणों का कारण बना है और अक्सर घातक होता है।
* इसलिए, स्तनधारियों के बीच H5N1 संचरण की हालिया रिपोर्टें, मानव महामारी का कारण बनने की इसकी क्षमता के बारे में चिंताएँ उठाती हैं

## H5N1 का इंट्रा-स्तनपायी संचरण :

* हाल ही में, मिंक फार्मों में कैद H5N1 का इंट्रा-स्तनपायी संचरण दर्ज किया गया था, जो जूनोटिक क्षमता से संबंधित एक बड़ी चिंता का विषय था।
* हाल ही में फरवरी 2023 में, पेरू ने सी-लायन और डॉल्फ़िन में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा के मामलों की सूचना दी, और एक चिड़ियाघर में H5N1 से एक शेर की मृत्यु हो गई।
* यह H5N1 के मनुष्यों में महामारी का कारण बनने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है यदि यह फैल गया और मनुष्यों के बीच संचरित हो गया।

## पिछले आउट ब्रेक :

* H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस पहली बार 1996 में चीन में एक बत्तख के खेत में पाया गया था।
* इसके बाद, 1997 में हांगकांग में पोल्ट्री के बीच एक बड़े प्रकोप की सूचना मिली, जिससे H5N1 का मानव संक्रमण भी हुआ, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 18 संक्रमित हो गए।
* 2004 में, H5N1 एशिया के कई देशों में रिपोर्ट किया गया था, और इसके अलावा, एक वैश्विक प्रकोप आज भी जारी है।
* 2013 और 2014 में, यूरोप और एशिया के कई देशों ने पोल्ट्री में H5N1 की सूचना दी।
* पिछले कुछ वर्षों में वायरस ने दुनिया भर में प्रकोप पैदा किया है, मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलाया गया है।
* आज तक, मानव H5N1 संक्रमण के 800 से अधिक मामलों की भी सूचना मिली है, जिसमें 53% की उच्च मृत्यु दर है।

## भारत में एवियन फ्लू का प्रकोप :

* भारत में, 2020-2021 में नवीनतम प्रमुख एवियन फ्लू का प्रकोप कई राज्यों में फैल गया, जिससे जंगली पक्षियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई, जिससे सक्रिय निगरानी की कमी पर चिंताएँ सामने आईं, और पोल्ट्री के इंटरफेस में आर्द्रभूमि और जलपक्षी आवास कैसे होने चाहिए।

## भारत के लिए चुनौतियां :

* मध्य एशियाई फ्लाईवे का उपयोग करने वाले कई जलपक्षी के लिए भारत एक प्रमुख शीतकालीन आवास है।
* जबकि एवियन फ्लू का प्रकोप पीक प्रवासी मौसम के साथ मेल खाता है, जिसके कारण प्रकोप के बाद की निगरानी और मुर्गियों को मारना होता है, पोल्ट्री क्षेत्र के भीतर स्थानिक संचरण का सुझाव देने वाले ऑफ-सीज़न में प्रकोप की भी रिपोर्टें हैं।
* भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंडा उत्पादक है, लेकिन यूरोप के विपरीत, यहां पोल्ट्री पक्षियों को फ्लू के खिलाफ टीका नहीं लगाया जाता है।
* इसके अलावा, जानवरों की विविधता वाले खेतों या आस-पास के आर्द्रभूमि के आसपास के क्षेत्रों में वायरस के पुन: वर्गीकरण से गुजरने की संभावना बढ़ जाती है जो संभावित रूप से अधिक विषाणुजनित उपभेद H5N1 या H7N9 उत्पन्न कर सकते हैं - जो तब मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं।
* इस संभावना के बावजूद पोल्ट्री क्षेत्र में कोई सक्रिय निगरानी नहीं है।
* मानव-से-मानव संचरण तंत्र अभी तक कोई कुशल मानव-से-मानव संचरण तंत्र नहीं हो सकता है, हालांकि, जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वायरस का विकास जारी है।
* हमें वन हेल्थ के तहत एक सक्रिय और निष्क्रिय साल भर निगरानी नेटवर्क की आवश्यकता है जो एक साझा वातावरण में मानव और जानवरों की निगरानी को जोड़ता है।

## अपशिष्ट जल आधारित महामारी विज्ञान या रोगजनक निगरानी:

* अपशिष्ट जल-आधारित महामारी विज्ञान या रोगज़नक़ निगरानी पर्यावरण निगरानी का एक अभिन्न अंग बन गया है जो रोगजनकों के स्वास्थ्य और सामुदायिक जोखिम पर लगभग वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
* जबकि पर्यावरण निगरानी कोई नई अवधारणा नहीं है और कई रोगजनकों की निगरानी के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, यह एक उत्कृष्ट उपकरण प्रदान करता है।
* वायरस के साथ पशु मेजबानों के बार-बार होने वाले संक्रमण ने लगातार खतरा पैदा किया है।
* विविधता के बारे में हमारी समझ में सुधार के लिए, और पोल्ट्री और जंगली पक्षियों से जुड़े वातावरण में वायरस के मौसमी और भौगोलिक वितरण के लिए कई साइटों पर एक वायरस निगरानी नेटवर्क महत्वपूर्ण है।
* निगरानी को उन स्थानों को लक्षित करने की आवश्यकता है जहां स्पिलओवर की सबसे अधिक संभावना है।
* घरेलू बत्तखों को H5N1 के लिए एक महत्वपूर्ण जलाशय के रूप में पहचाना जाता है।

## पश्चिमी गोलार्ध:

* H5N1 फैलने और प्रकोप को रोकने के लिए उपायों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं
* पोल्ट्री का टीकाकरण
* मृत पक्षियों का सुरक्षित निपटान
* प्रभावित पशुओं को संगरोध और मारना
* पक्षियों को संभालते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना
* पक्षियों और अन्य जानवरों में H5N1 की बेहतर निगरानी और निगरानी
* H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा के खिलाफ मानव टीकों को बीमारी के सबसे गंभीर रूपों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
* हालांकि, एच5एन1 वायरस की अत्यधिक परिवर्तनशील प्रकृति संभावित रूप से समय के साथ टीके की प्रभावकारिता को कम कर सकती है।
* इसलिए, एवियन इन्फ्लूएंजा और इसके उपप्रकारों की आणविक निगरानी प्रकोपों को समझने और प्रतिक्रिया देने में आवश्यक है।

## निष्कर्ष:

* हालांकि H5N1 के संक्रमित होने और मनुष्यों के बीच फैलने का जोखिम कम के रूप में मूल्यांकन किया गया है, एवियन इन्फ्लूएंजा को नियंत्रित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में रोग और जीनोमिक निगरानी के प्रकोप पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।
* जैसा कि हमने COVID-19 के प्रकोप से सीखा है, आकार बदलने वाले वायरस के विकास की निगरानी एक और संभावित महामारी के खिलाफ तैयारियों में इजाफा कर सकती है।
* वर्तमान में, वायरस निगरानी प्रतिक्रियाशील है और मृत पक्षियों के नमूने लेने पर निर्भर करती है।

**प्रश्न:**17 क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? इसे व्यापक रूप से सामाजिक और आर्थिक संकटों के लिए क्यों दोषी ठहराया जाता है। आलोचनात्मक विश्लेषण (150 शब्द)

* **भारत की दुविधा: आर्थिक एकाग्रता के जोखिम को कम करना - समसामयिकी लेख**

## प्रसंग:

* भारत एक आर्थिक मॉडल की ओर स्थानांतरित हो गया है जिसमें 'राष्ट्रीय चैंपियन' की एक छोटी संख्या है - प्रभावी रूप से बड़े निजी कुलीनतंत्र जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करते हैं।

## विश्व मंच पर भारत की क्षमता:

* अपनी विशाल और बढ़ती आबादी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद चीन की तुलना में केवल एक-चौथाई होने के कारण, भारत में आर्थिक विकास और उत्पादकता में वृद्धि की जबरदस्त क्षमता है।
* भारत के लोकतंत्र से अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी सॉफ्ट पावर उत्पन्न होने की उम्मीद है , जबकि इसके सैन्य और भू-राजनीतिक महत्व को और बढ़ने का अनुमान है।
* सरकार उन नीतियों को लागू कर रही है जिनसे भारत का आधुनिकीकरण हुआ है और इसके विकास में मदद मिली है।
* कोविड मंदी के बाद मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को बुनियादी ढांचे में निवेश, घरेलू विनिर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों, प्रौद्योगिकी और आईटी में भारत के तुलनात्मक लाभ और एक अनुकूलित डिजिटल-आधारित कल्याण प्रणाली के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

## भारत की विकास संभावनाओं के लिए जोखिम:

* वही मॉडल जिसने भारत के विकास को प्रेरित किया था, अब इसमें बाधा डाल सकता है, क्योंकि इसके विकास की संभावनाओं के जोखिम व्यापक आर्थिक या चक्रीय कारकों के बजाय सूक्ष्म और संरचनात्मक कारकों में निहित हैं।
* भारत एक आर्थिक मॉडल की ओर स्थानांतरित हो गया है जिसमें 'राष्ट्रीय चैंपियन' की एक छोटी संख्या है - प्रभावी रूप से बड़े निजी कुलीनतंत्र जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करते हैं।
* यह प्रवृत्ति सुहार्तो (1967-98) के तहत इंडोनेशिया, हू जिंताओ (2002-12) के तहत चीन, या 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया से मिलती-जुलती है, जहां प्रमुख चैबोल ( अमीर परिवार ) आदर्श थे।
* आर्थिक शक्ति के इस संकेन्द्रण से भारत को कुछ हद तक लाभ हुआ है। चीन की तुलना में निवेश दर (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) बहुत कम होने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है।
* हालांकि, इस आर्थिक मॉडल का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये समूह अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माण पर प्रभाव डालने में सक्षम रहे हैं।

## मॉडल के संभावित परिणाम:

* **इस आर्थिक मॉडल के दो प्रमुख और नकारात्मक परिणाम हुए हैं:**
* सबसे पहले, यह नवाचार को दबा रहा है और प्रमुख उद्योगों में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप और घरेलू प्रवेशकों को अनिवार्य रूप से समाप्त कर रहा है
* दूसरा , यह सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को एक अनुत्पादक और संरक्षणवादी पहल में बदल रहा है।
* ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की विकास क्षमता में तेजी आने के बजाय गिरावट आई है , जो ऊपर बताए गए नकारात्मक प्रभावों का परिणाम हो सकता है।
* 1980 और 1990 के दशक में एशियन टाइगर्स ने विनिर्मित वस्तुओं के सकल निर्यात के आधार पर विकास मॉडल के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी तरह भारत ने तकनीकी सेवाओं के निर्यात के साथ भी ऐसा ही किया है।
* 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत के व्यापार योग्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
* हालाँकि, भारत एक अधिक संरक्षणवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है जो एक राष्ट्रवादी स्वर के साथ घरेलू उत्पादन के लिए आयात-प्रतिस्थापन और सब्सिडी को प्राथमिकता देता है।
* ये नीतियां घरेलू उद्योगों और समूहों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचा रही हैं, लेकिन वे अपनी टैरिफ नीतियों के कारण माल के निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी बाधा बन रही हैं । इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में भाग लेने की भारत की अनिच्छा वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसके पूर्ण एकीकरण में बाधा बन रही है।
* 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के सामने एक और चुनौती है क्योंकि यह कार, ट्रैक्टर और ट्रेनों जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने की ओर स्थानांतरित हो गया है। भारत को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उसे तुलनात्मक लाभ है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, तकनीक और आईटी सेवाएं।
* भारत को स्कूटर जैसे कम पारंपरिक उद्योगों और अधिक स्टार्टअप की आवश्यकता है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर केंद्रित हैं।
* इन गतिशील क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, नीति निर्माताओं को विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए, जैसा कि अन्य सफल एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किया जाता है । इस तरह के सुधारों के बिना, 'मेक इन इंडिया' उप-इष्टतम परिणाम देना जारी रखेगा।

## निष्कर्ष:

* एशियाई वित्तीय संकट ने इस बात का प्रमाण दिया कि क्रोनी पूंजीवादी समूहों द्वारा आर्थिक नीतियों का आंशिक नियंत्रण उत्पादकता वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
* यह प्रतियोगिता में बाधा डालने , शुम्पीटरियन के 'रचनात्मक विनाश' को दबाने और धन की खाई को चौड़ा करने से होता है।
* इसलिए भारत सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसी रास्ते पर चलने से बचे।
* दीर्घावधि में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह ऐसा विकास मॉडल स्थापित और कायम रख सकता है जो समान, समावेशी, टिकाऊ, गतिशील और प्रतिस्पर्धी हो।

**प्रश्न:**18 महंगे आयात पर अंकुश लगाने के लिए तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाना महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर सुझाव दें। (150 शब्द)

* **तिलहन क्षेत्र को पुनर्जीवित कैसे किया जाए - समसामयिकी लेख**

## संदर्भ:

* सरकार, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्सुक है ताकि पुरानी घरेलू कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक 14 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 13-14 मिलियन टन वनस्पति तेल आयात के बोझ को कम किया जा सके।

## मुख्य विशेषताएं:

* देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अल्पावधि में आयात अपरिहार्य रूप में है।
* हालांकि, वर्तमान आयात नीतियां उपभोक्ताओं के हित को प्राथमिकता देती हैं और स्थानीय तिलहन किसानों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करती हैं।
* अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, एक ऐसी नीति का पालन करना चाहिए, जो एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए और उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखे।
* भूमि प्रतिबंधों, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन की सयुक्त चुनौतियों को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

## पहल जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है:

* घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना अपरिहार्य है, जिसके लिए प्रभावी नीतिगत उपाय महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित छह पहल जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं: –
* खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च-इनपुट अनाज मोनो-क्रॉपिंग क्षेत्रों में फसल रोटेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
* इन्फोटेक, सैटेलाइट टेक, न्यूक्लियर एग्रीटेक और नैनोटेक सहित कई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए।
* उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए बेहतर बीज प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
* किसानों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रव्यापी खरीद प्रणाली की स्थापना करनी चाहिये।
* गैर-पारंपरिक तेल स्रोतों जैसे कि कपास के बीज, चावल-चोकर और पेड़-जनित तिलहन की अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाना चाहिए।
* क्रशिंग और निष्कर्षण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने में निवेश करना चाहिए।
* हालाँकि इनमें से हर उपाय को हासिल किया जा सकता है, मगर हो सकता है कि उनका सकारात्मक असर तुरंत न दिखे। इसलिए, कुछ "त्वरित लाभ प्राप्त होने वाले पहल" की पहचान करना भी आवश्यक है जिन्हें तत्काल लाभ देने के लिए लागू किया जा सकता है।

## 'त्वरित लाभ' के लिए नीतिगत क्रियाएँ:

* **वनस्पति तेल के आयात को विनियमित और मॉनिटर करना:** वर्तमान में, प्रासंगिक डेटा के समर्थन के बिना, नीतिगत हस्तक्षेप आवेगपूर्ण और प्रतिक्रियाशील होते हैं।
* हालांकि, "आयात अनुबंध पंजीकरण" के लिए एक सीधी प्रशासनिक प्रणाली को लागू करके और आयात की बारीकी से निगरानी करके, व्यापार में पारदर्शिता की कमी को समाप्त किया जा सकता है, और भारत सरकार सूचित, डेटा-संचालित निर्णय ले सकती है।
* **विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की क्रेडिट अवधि को अधिकतम 45 दिनों तक कम करना:** 90-120-150 दिनों की क्रेडिट अवधि अत्यधिक व्यापार और अटकलों को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कुछ भारतीय आयातकों के लिए "आयात ऋण जाल" उत्पन्न हो सकता है। इन आयातकों पर बैंक ऋणों के चूक का खतरा है, जिससे वे संभावित रूप से गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन सकते हैं।
* क्रेडिट अवधि को कम करके, आयात की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी, और आयातक अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह हो जाएंगे, जिससे डिफ़ॉल्ट का जोखिम कम हो जाएगा।
* **खाना पकाने के तेल को पीडीएस के तहत लाना:** आबादी के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए, सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्य तेल की आपूर्ति करनी चाहिए।
* सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और निजी व्यापार चैनल दोनों सह-अस्तित्व में रह सकते हैं और उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर सकते हैं।
* **तिलहन आयात की अनुमति देना:**कई लाभ प्राप्त करने के लिए, सरकार वनस्पति तेल आयात के आंशिक विकल्प के रूप में तिलहन के आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।
* इस दृष्टिकोण से निष्क्रिय घरेलू प्रसंस्करण क्षमता के उपयोग में वृद्धि होगी, खाद्य तेल की उपलब्धता में वृद्धि होगी, और महत्वपूर्ण रूप से, घरेलू पशुधन क्षेत्र या निर्यात के लिए अधिक भोजन प्रदान किया जा सकता है।
* **तिलहन प्रसंस्करण उद्योग आधुनिकीकरण कोष बनना:** 15,000 तिलहन क्रशिंग इकाइयों और 800 विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में से कई पैमाने, उपकरण, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता के मामले में आंतरिक रूप से अक्षम हैं।
* एक आधुनिक उद्योग अधिक मूल्य प्राप्त करेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता पैदा करेगा।
* **पिछड़ा एकीकरण:**आयात पर निर्भर बड़ी प्रसंस्करण इकाइयों को एफपीओ के साथ काम करके तिलहन का उत्पादन करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करना चाहिए।

## निष्कर्ष :

* हालांकि नई ऑयल पाम पहल एक स्वागत योग्य कदम है, निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रचार नीति की व्यापक समीक्षा करना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
* तिलहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और मौजूदा यथास्थिति को रचनात्मक रूप से बाधित करना आवश्यक है।
* इसे प्राप्त करने के लिए, नीति निर्माताओं को तिलहन क्षेत्र को प्राथमिकता देने और नीति, निवेश और अनुसंधान सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
* ऐसा करके, देश पर्याप्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है और उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को समान रूप से बढ़ावा दे सकता है।

**प्रश्न:**19 छठी अनुसूची क्या है? लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के रूप में क्षेत्र की स्थिति से असंतुष्ट क्यों हैं? (250 शब्द)

* **लद्दाख, एक नाजुक क्षेत्र, जिसे स्वायत्तता की जरूरत है - समसामयिकी लेख**

## संदर्भ:

* संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के तीन साल बाद, नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोगों के कुछ वर्ग, फिर से राज्य का दर्जा और विकास परियोजनाओं में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे नौकरशाही के अधिक हस्तक्षेप के कारण खुद को अक्षम महसूस कर रहे हैं।

## लद्दाख के बारे में:

* लद्दाख में बड़े ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र शामिल हैं।
* यह लगभग 45,000 वर्ग मील तक फैला है और पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है।
* लोकप्रिय रूप से यह "दर्रों की भूमि" के रूप में जाना जाता है, इसमें लगभग 3 इंच (80 मिमी) की औसत वार्षिक वर्षा के साथ एक ठंडी और शुष्क जलवायु है।
* यहाँ भयंकर सर्दियां होती है और यह दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है।

## लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के रूप में क्षेत्र की स्थिति से असंतुष्ट क्यों हैं?

* कई लद्दाखियों ने महसूस किया है कि अपेक्षाकृत स्वतंत्र और स्वायत्त कामकाज और पर्याप्त स्थानीय रोजगार सृजन की उनकी वास्तविक आवश्यकता अभी भी एक मृगमरीचिका है।
* लंबे इतिहास की स्मृति: 1,000 वर्षों तक, लद्दाख जम्मू और कश्मीर (J & K) में एकीकृत होने से पहले एक स्वतंत्र राज्य था।
* इस लंबे इतिहास की स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता है, हाल ही में यह बदलाव हुआ है कि यह अब जम्मू-कश्मीर के अधीन नहीं है, लद्दाख पर अब नई दिल्ली का शासन है।
* **छठी अनुसूची का दर्जा अभी तक नहीं मिला है:** लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एएचडीसी) चुनाव से पहले, इस क्षेत्र को छठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा किया गया था, जैसा कि उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों को प्राप्त है।
* यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
* **क्षेत्र की संवेदनशीलता:** लद्दाख की संवेदनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र में जंगली याक और हिम तेंदुए और विविध वनस्पतियों जैसे दुर्लभ स्तनधारी हैं।
* संस्कृतियों और आजीविकाओं का विकास पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता के प्रति संवेदनशील होने के लिए हुआ है जो भारी मानव गतिविधि को सहन नहीं कर सकता है।
* उच्च ऊंचाई वाले पशुपालन, कृषि और व्यापार, सदियों से लद्दाखी अर्थव्यवस्था और समाज के मुख्य आधार रहे हैं।
* **बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि:** लद्दाख पहले से ही बुनियादी ढांचे के विकास, तीव्र सशस्त्र बलों की उपस्थिति और अत्यधिक पर्यटन से कराह रहा है।
* जब से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से शोषणकारी 'विकास' पथ पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
* खनन, पर्यटन, जल विद्युत और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में भारी वाणिज्यिक रुचि रखी गई है।
* केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस क्षेत्र में निवेश आमंत्रित कर रहा है, और भारत के सबसे बड़े निगम इस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने के लिए रुचि दिखा रहे हैं।
* यहां एक नया हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, और अपेक्षाकृत अप्रयुक्त ज़ांस्कर क्षेत्र सहित सड़क निर्माण में तेजी लाई गई है।
* लद्दाख पहले से ही भूस्खलन, कटाव, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट, वन्यजीवों के लिए अशांति और विकास परियोजनाओं के लिए आम भूमि के अधिग्रहण की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है।
* कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के नाम पर मेगा-सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 2023 के बजट में पारिस्थितिक रूप से नाजुक चांगथांग क्षेत्र में 13 GW की परियोजना से सौर ऊर्जा निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

## छठी अनुसूची क्या है?

* छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान हैं।
* 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित, यह स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है।
* एडीसी एक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं जिन्हें संविधान ने राज्य विधायिका के भीतर स्वायत्तता के अलग-अलग अधिकार दिए है।
* इन राज्यों के राज्यपालों को आदिवासी क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का अधिकार है।
* सरल शब्दों में, वह किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने, सीमाओं को बढ़ाने या घटाने और दो या दो से अधिक स्वायत्त जिलों को एक में एकजुट करने का विकल्प चुन सकते है।
* वे एक अलग कानून के बिना ही स्वायत्त क्षेत्रों के नाम भी बदल सकते हैं या बदल सकते हैं।

## स्वायत्त जिले और क्षेत्रीय परिषद

* एडीसी के साथ-साथ छठी अनुसूची में एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है।
* कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर में 10 क्षेत्र हैं जो स्वायत्त जिलों के रूप में पंजीकृत हैं – तीन असम, मेघालय और मिजोरम में और एक त्रिपुरा में। इन क्षेत्रों को जिला परिषद (जिले का नाम) और क्षेत्रीय परिषद (क्षेत्र का नाम) के रूप में नामित किया गया है।
* प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और बाकी चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होते हैं।
* वे सभी पांच साल की अवधि के लिए सत्ता में रहते हैं।
* बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, हालांकि, एक अपवाद है क्योंकि यह 46 सदस्यों का गठन कर सकता है जिनमें से 40 चुने जाते हैं।
* इन 40 सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जनजातियों और गैर-जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षित हैं, पांच अनारक्षित हैं और शेष छह बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र जिले (बीटीएडी) के गैर-प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से राज्यपाल द्वारा नामित हैं।

## एडीसी को नागरिक और न्यायिक शक्तियों का अधिकार

* एडीसी को नागरिक और न्यायिक शक्तियों के साथ सशक्त किया गया है, जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्राम अदालतों का गठन कर सकते हैं। छठी अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इनमें से प्रत्येक मामले के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हैं।
* परिषदों को भूमि, वन, मत्स्य पालन, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे मामलों पर राज्यपाल से उचित अनुमोदन के साथ विधायी कानून बनाने का भी अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका इन स्वायत्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से प्रतिबंधित है।
* इसके अलावा, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों को इन क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के कानूनों में संशोधन के साथ उनकी स्वीकृति नहीं देते हैं।

## आगे की राह :

* लद्दाख और दिल्ली के लिए एक साथ काम करने के अवसर हैं।
* लद्दाख कृषि को पूरी तरह से जैविक बनाने के लिए एक पहाड़ी परिषद के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा समर्थित किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों को स्थानीय रूप से उगाई गई और बनाई गई वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता होती है)।
* समुदायों को वन अधिकार अधिनियम का उपयोग करके घास के मैदानों पर सामूहिक अधिकारों का दावा करने और संचालित करने में सहायता की जा सकती है।
* पर्यटन पूरी तरह से समुदाय द्वारा संचालित, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील यात्रा की ओर उन्मुख हो सकता है।

## निष्कर्ष :

* लद्दाखी नागरिक समाज संगठन और कुछ सरकारी विभाग पहले से ही क्षेत्र की पारिस्थितिकी, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उपयोग, खाद्य और कृषि विरासत, उद्यमिता और बहुत कुछ के प्रति संवेदनशील आजीविका के लिए अद्भुत पहल लागू कर रहे हैं।
* एक संवैधानिक दर्जा जो एक संवेदनशील स्थानीय आबादी द्वारा संचालित स्थानीय रूप से निर्धारित मार्गों को सक्षम बनाता है, उस विनाशकारी ट्रैक से बचने में मदद कर सकता है जिस पर भारत के कई अन्य हिस्से चले जाते हैं।

**प्रश्न:**20 संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत अधिकारों और सांप्रदायिक अधिकारों के बीच संघर्षों को हल करने में कैसे भूमिका निभा सकती है? चर्चा कीजिये

**कानून का मर्म असहमतिपूर्ण निर्णय में निहित है - समसामयिकी लेख**

* सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कृत करने की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को 28 सितंबर, 2018 के सबरीमाला फैसले की समीक्षा के लिए गठित नौ न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया।

## धर्म से बहिष्कृत करना:

* कानून ने "किसी भी समुदाय से किसी व्यक्ति के निष्कासन को परिभाषित किया है कि, निष्कासन से व्यक्ति उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित हो जाता है जो नागरिक प्रकृति के मुकदमे द्वारा कानूनी रूप से लागू होना चाहिए।"
* व्यावहारिक रूप से, बहिष्कृत करने का मतलब है कि समुदाय से संबंधित पूजा स्थल या अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

## मुद्दा क्या है?

* धार्मिक समूहों के अधिकारों को उनके अनुयायियों के अधिकारों के साथ कैसे संतुलित किया जाए, यह सवाल भारत की अदालतों में लंबे समय से एक मुद्दा रहा है।
* 1962 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के फैसले में, सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर समूह अधिकारों को प्राथमिकता दिया था।
* इस मामले ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट, 1949 को चुनौती दी, जिसने धार्मिक समुदायों को समूह की सदस्यता से व्यक्तियों को निष्कासित करने से रोक दिया था।
* याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बहिष्कृत करने की शक्ति दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता के सामूहिक अधिकार का अभिन्न अंग है।
* भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दाऊदी बोहरा समुदाय बनाम महाराष्ट्र राज्य के केंद्रीय बोर्ड के फैसले के माध्यम से सरदार सैयदना के फैसले पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।

## पुनर्विचार के कारण:

* मूल फैसला इस बात की जांच करने में विफल रहा था कि क्या धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों को अन्य मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जबकि इसके इसके व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों को समान देखभाल और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।
* सरदार सैयदना के बाद के वर्षों में, भारतीय न्यायमूल्य एक ऐसे बिंदु पर विकसित हुआ है जहां किसी भी तरह के बहिष्कार को संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

## भारत में, संघर्ष अपरिहार्य है:

* कनाडा की पूर्व मुख्य न्यायाधीश बेवर्ली मैकलाचलिन के शब्दों में, धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं को मापने के लिए कोई "जादुई बैरोमीटर" नहीं है।
* धर्म भारत के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी कारण, सांप्रदायिक व्यक्तिगत अधिकार अक्सर समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों के साथ टकराते हैं।
* 1954 के शिरूर मठ मामले में, अदालत ने कहा कि धर्म के केवल उन पहलुओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा जो उस धर्म के विश्वास के लिए आवश्यक माने जाते हैं।
* मगर धार्मिक और धर्म-निरपेक्ष के बीच का यह भेद जल्द ही टूट गया, क्योंकि अदालत ने धार्मिक शास्त्रों की व्याख्या करने और यह तय करने का धार्मिक अधिकार ग्रहण कर लिया कि कौन-सी प्रथाएँ विश्वास का अभिन्न अंग हैं।
* यह तरीका त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसने व्यक्ति की नैतिक स्वायत्तता को यह निर्धारित करने के लिए नजरअंदाज कर दिया कि उनके जीवन का नेतृत्व कैसे किया जाए।
* सरदार सैयदना मामले ने इस समस्या को और उजागर किया क्योंकि अदालत व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथा को केवल इसलिए रद्द करने में विफल रही क्योंकि इसे विश्वास के लिए आवश्यक माना जाता था।

## आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत की विफलता

* आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत का अर्थ यह भी था कि न्यायालय कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथा को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था, यदि इसे विश्वास के लिए आवश्यक समझा गया हो।
* यह सरदार सैयदना मामले में स्पष्ट था, जहां दाऊदी बोहरा समुदाय के नेता ने 1949 के बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट को चुनौती दी थी।
* न्यायालय ने कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि समूह के विश्वास के लिए बहिष्कृत करने की शक्ति इतनी आवश्यक थी कि कानून, अपने अस्तित्व से बाहर धर्म में सुधार नहीं कर सकता था।

## सरदार सैयदना में असंतोष

* सरदार सैयदना मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.पी.सिन्हा ने एक असहमति पूर्ण राय पेश की जिसमें व्यक्ति के महत्व पर जोर दिया गया।
* उन्होंने तर्क दिया कि यह अप्रासंगिक था कि धर्म के लिए बहिष्कृत करने की प्रथा आवश्यक थी या नहीं।
* इसके बजाय, अदालत को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रथा का बहिष्कृत व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा।
* बहिष्कृत होने के परिणामस्वरूप व्यक्ति को सांप्रदायिक संपत्तियों का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया और सामाजिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया।
* इस प्रथा ने संविधान के अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन किया, जिसने किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है।
* सीजेआई ने तर्क दिया कि धार्मिक समूहों के पास अधिकार हैं ताकि व्यक्ति सामूहिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक साथ आ सकें, और कोई भी अभ्यास, चाहे विश्वास के लिए कितना भी आवश्यक हो, व्यक्ति की गरिमा को कम नहीं कर सकता है।

## संवैधानिक नैतिकता का महत्व:

* संवैधानिक नैतिकता यह विचार है कि भारत का संविधान न केवल कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, बल्कि नैतिक रूप से भी उचित होना चाहिए।
* इसमें स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और गरिमा के मूल्य शामिल हैं जो संविधान की नींव बनाते हैं।
* हाल के वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों और सांप्रदायिक अधिकारों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए संवैधानिक नैतिकता पर भरोसा किया है।
* संविधान के अनुच्छेद 26 में प्रावधान है कि सभी धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप होना चाहिए।
* संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि धार्मिक प्रथाओं को संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाए, जिसमें सभी व्यक्तियों की गरिमा और समानता भी शामिल है।

## निष्कर्ष :

* धार्मिक समूहों के अधिकारों को उसके व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकारों के साथ संतुलित करना भारत में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
* आवश्यक प्रथाओं का सिद्धांत विफल हो गया क्योंकि इसने सदस्यों की स्वायत्तता को कम कर दिया और कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं को रद्द करने में बाधा पहुचता है।
* न्यायालय धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व को पहचानता है, लेकिन व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को भी स्वीकार करता है कि कोई भी अभ्यास उनकी नैतिक स्वायत्तता को कम नहीं करता है।
* अदालत इस मुद्दे को हल करने में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका पर विचार करेगी, और संभवतः एक समाधान की तलाश करेगी जो धार्मिक अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना सके।